

Haryana Vidhan Sabha

Debates

12th February, 1971

(Evening Sitting)

Vol. I—No. 6

OFFICE REPORT

CONTENTS

Friday, the 12th February, 1971 (Evening Sitting)

	Page
Starred questions and Answers	(6)1
Second Report of the Business Advisory committee	(6)24
Presentation of Reports	(6)26
Bills(s)—	
The Haryana Appropriation—1971	(6)27
The Public works (Extension of Limitation) Haryana Amendment—1971	(6)55
The Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment)—1971	(6)57
The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment)—1971	(6)70
The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment)—1971	(6)73
The Haryana Prevention of Beggary—1971	(6) 75-89

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 12th February, 1971 (Evening Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh at 2-00 P.M. of the Clock.

Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair

STARRED QUESTION AND ANSWERS

Mr. Speaker: Hon. Members, the question Hour. Sh. Daya Krishan

(The hon. Member was not present in the House.)

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of Starred Q. No. 1156. Next Question. Dr. Malik Chand Gambhir.

Removal of cut imp[osed on D.A. to Teachers

***116 Dr. Malil Chand Gambhir:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the cut imposed it the dearness allowance being paid along with the pay to the teachers in Haryana; if so, the time by which the said cut is likely to be removed?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Some teachers have filed writ in the High Court demanding restoration of cut. Government is awaiting decision of the High Court.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या यह बगैर रिट के फैसला नहीं हो सकता था? क्या सरकार इस कट को नाजायज नहीं समझती, अगर समझती है तो इस कट को 'रेस्टोर' कर दिया जाये।

श्री माडू सिंह मलिक: नहीं जी।

श्रीमती चन्द्रावती: वजीर साहिब ने जो आरिजीनल सवाल का उत्तर दिया है क्या वह उसको दोहरायेंगे?

Sh. Maru Singh Malik: Some teacher have filed writ in the Hight Court demanding restorationof cut. Government is awaitig decision of the High Court.

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि रिट से पहले सरकार ने इस बारे में कोई फैसला किया है या नहीं किया और अगर फैसला ही किया तो उसका क्या कारण है?

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहिब, मैं जानना चाहती हूंकि क्या रिट के फसेले से पहले इस बारमें में फैसला करने में कोई कानूनी अड़चन आती है?

श्री माडू सिंह मलिक: जी हां।

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि क्या रिट दायर हाने से पहले सरकार के पास वह मांग नहीं थी?

श्री माडू सिंह मलिक: रिट दायर होने से पहले मांग थी। लेकिन फैसला होने से पहले रिट दायर कर दी गई थी।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर साहब, क्या रिट होने के बाद फैसला नहीं हो सकता है? अब भी अगर यह सरकार फैसला कर देती है तो रिट आटोमैटिकली खारिज हो जाएगी without any burden on the State regarding cost etc. यह जो इन्होंने कहा कि रिट का फैसला होने के बगैर सरकार कुछ नहीं करेगी यह बात ठीक मालूम नहीं होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फर्ज करो, रिट खारिज हो जाती है तो क्या गवर्नमेंट इस मामले को फिर कन्सीडर करेगी?

श्री माडू सिंह मलिक: यह मौके मुताबिक देख लिया जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन करने और रिट दायर करने के बीच का कितना अरसा था?

श्री माडू सिंह मलिक: इसके लिए अलग नोटिस चाहिए।

Mr. Speaker: I think, it is a reasonable question. You have said yourself that it was under consideration. Then in the meantime, they filed a writ and, therefore, you do not consider anything is to be done now. I think, if you know that, you may give this information of the House.

Sh. Maru Singh Malik: I do not remember it. जनाब, तारीख मुझे पता नहीं किस तारीख को रिट दायर की गई थी।

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): That makes no difference as to what time was there. That is an irrelevant supplementary.

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तथ्यों की जानकारी का फर्क है। तभी सवाल किया है। फर्ज करों सरकार के खिलाफ फैसला आ जाता है। तो क्या इतना अरसा सरकार सोई रही है? क्या यह हमारे प्रदेश के हितों के खिलाफ नहीं है कि यदि उनकी गलत जानकारी के कारणहाई कोर्ट सरकार के विरुद्ध फैसला कर दें? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि कितनी देर रिप्रेजेंटेशन सरकार के जेरे गौर रिट के दायर होने से पहले रही?

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहिब, मैम्बर महोदय को सोने का भय है, सरकार सोई नहीं है। The Government is fully aware of its responsibilities.

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री जी से मैं इतनी बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई सदस्या प्रश्न करता है तो इसमें कोई सोने और जागने की बात नहीं है मैं इस हाउस का सदस्य हूँ, यह तो एक सदस्य का अधिकार है। मैंने अपने अधिकार को बरतते हुए पूछा है।

श्री बंसी लाल: मैं भी इस हाउस का सदस्य हूँ। वह अकेले सदस्य नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, आपने मुझे बुलाया, मैं बोला। एक या दस या पंद्रह सवाल नहीं है। यह तो बार बार ऐसी बात करते हैं। क्या यह मुख्य मंत्री के कहने के नायल बात है? यही जवाब है इन के पास?

Mr. Speaker: What they have said is that they were well aware of the matter and they were not sleeping at all.

श्री सत्य नारायाण सिंगोल: जनाब बात यह है कि उन्होंने कहा कि रिट के फैसले के बाद गौर करेंगे। फर्ज करों होई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिट का फैसला स्टेट के खिलाफ हो जाता है और विद कास्ट हो जाता है तो उससे स्टेट पर बर्डन भी पड़ेगा। पहले उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी फिर पर्सनली मीट करने के बाद रिट दायर की। बहुत अरसे तक उन्होंने इसबात को सोचा तक नहीं, अपनी जिद पर अड़े रहे। यदि हाई कोर्ट का सरकार के खिलाफ फैसला हो जाता है तो इन की गलती से पब्लिक क्यों सफर करे। तो हम जानना चाहते हैं कि इस चीज के लिए इनको कितन टाईम मिला था?

Sh. Bansi Lal: You cannot go by conjectures, what will be the decision and what not.

डा मलिक चन्द गम्भीर: मुख्य मंत्री ने जवाब में बताया कि उन्होंने रिट कर रखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या रिट का जवाब दिया है।

श्री बंसी लाल: Not necessary to say दिया या नही दिया। हाई कोर्ट का फैसला आने पर पता लगेगा।

डा० मलिक चन्द गम्भीर: रिट का जवाब तो इन्होंने दिया है.....

Sh. Bansi Lal: It is a subjoined matter.

Mr. Speaker: I don't think it is going to benefit you much. Anyway, a writ is pending in the High Court. These are legal proceedings and they have given a reply to that one.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहिब, जो चौधरी रणबीर सिंह जी ने पूछा था औरउसे मै भी दोहरा दूं कि रिट और कट के बीच का कितना टाईम था? यह सूचना अगर अब नही दे सकते तो सोमवार का दिलवा दे।यह तो बड़ा मेटिरियल सवाल है.....
.....They cannot avoid it like this.

Sh. Bansi Lal: It is a quite immaterial. It is not material at all what time was thee and what not. When the Government wants to the take a decision, it can take a decision. A writ is pending in the High Court and the Government will not take a decision till the writ is pending.

श्रीमती चन्द्रावती: मेरी एक सबमिशन है, जनाब, जब वे रिट में गये है तो सरकार के फैसले का इन्तजार करके गये होंगे। इसलिए हम यह चाहते है कि कितना टाईम लाग? मै आपसे संरक्षण चाहूंगी.....(विधन)

श्री बसी लाल: स्पीकर साहिब, पहले आप इनको संरक्षण ही दे दो।

श्रीमती चन्द्रावती: जब मैं बोल रही हूँ तो ये बीच में बोलते हैं Why is he interfering like this? मुख्य मंत्री है तो इनको इतना अधिकार नहीं है कि वे मैम्बर को बोलने ने दे.....हम तो रिट और कट के बीच का टाईम जानना चाहते हैं।

Mr. Speaker: Why not ask a question as to when was the representation received by them? They might tell you about it.

Sh. Bani Lal: That has already been answered by the Hon. Minister that he does not remember it and it is not in the file. More over, it is quite immaterial.

Mr. Speaker: They wanted to know it.

Sh. Bansi Lal: They may want to know it. But it is quite immaterial.

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, इनको जवाब तो देना चाहिये।

Mr. Speaker: I have said that cannot force an answer. That is a ruling given earlier on. It is a ruling based on the precedents that I cannot force an answer. It is up to the good sense of the Hon. Minister himself whether to reply to the question or not.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहिब, वे तो उठना चाहते हैं जवाब देने के लिए लेकिन मुख्य मंत्री जी ने रोक दिया है।

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो रिट की कन्टेन्शन है और रिप्रेजेंटेशन में जो बात कही गई है उसमें क्या कुछ फर्क है? यदि है तो कितना फर्क है? और ऐसे कौन कौन से प्वायंट है जिनमें फर्क है?

(कोई जवाब नहीं)

Mr. Speaker: In any case, the matter is subjudice now and, I thin, let us leave it at that.

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा निवेदन करने का मतलब था कि जो मामला सब जुडिस है उस में सिर्फ रिट की कन्टेन्शन ही हो सकती है। रिट की कन्टेन्शन से बाहर तो उसमें कोई चीज सब जुडिस हो नहीं सकती?

श्री बंसी लाल: आनरेबल मैम्बर हाई कोर्ट से, पैसे देकर उस रिट की एक कापी ले आये।

Mr. Speaker: He has said that you may obtain a copy of their writ and their reply from the High Court.

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार से जवाब चाहता हूँ बाहर अन्दर का सवाल नहीं है, वहां से तो मिल सकती है।

श्री बंसी लाल: सरकार ने जवाब दे दिया है कि मामला सब जुडिस है।

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, मैंने एक सवाल किया वह यह कि जो रिट की कन्टेन्शन है और जो डिमान्ड उन्होंने गवर्नमेंट को भेजी है क्या वे एक ही चीज है या उसमें कोई फर्क है?

(कोई जवाब नहीं)

Mr. Speaker: They have said that the matter is subjudice and they do not want to answer any question.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर सहिब, इनका रिप्लाई ठीक नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर अगर हम कमेंट करें तो कन्टेन्शन आफ दी रिट स जुडिस नहीं होती। हम जानना चाहते हैं कि रिट क्या है और गवर्नमेंट ने उसका जवाब क्या दिया है? This is not a subjudice matter It can be replied and subould be replied.

श्री बंसी लाल: उसकी कापी हाई कोर्ट से मिलती है वहां से लो ले।

चौधरी जय सिंह राटी: स्पीकर साहिब, जैसा कि ये कहते हैं किरट है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहले ही अपने दिमाग में उन्होंने फैसला कर लिया है कि यह रिप्रेजेंटेशन एक्सैप्ट नहीं करती है?

Mr. Speaker: They taken a stand that the matter is sub juice.

चौधरी जय सिंह राठी: स्पीकर सहिब, सब जुडिस वह मैटर होता है जिसमें कसे कोई चीज बताने से इन्साफ यानी जस्टिस होने में कोई असर पड़ जाये। जैसे फर्ज कीजिए के मुलजिम चोरी का है। रिट में तो ब्यान दिया जाये कि उसने चोरी नहीं की और असल में ऐसा हो कि उसने चोरी की हो। तो ऐसी बात बाहर बताने से उसका इन्साफ पर असर पड़ता है। लेकिन रिट को देखते हुए ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे उसके फैसले पर असर पड़े। आपने किसी हद तक उनका जवाब मान है। और that is a written thing and not sub judice.

(No reply was given)

Mr. Speaker: Sub rule (12) of Rule 46 of our rules procedure reads—

“In order that a question may be admissible it shall satisfy the following conditions, normally:-

It shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the public or in ordinary works of reference;”

चौधरी जय सिंह राठी: मैंने जो बात कही है, वह सब जुडिस वाली बात नहीं है। यह बेशक कह दें कि हम तो जवाब ही नहीं देना चाहते लेकिन They should not take this shelter. My only contenton is that they should distinguish what can be sujudice and what can be available in the open market or anywhere else. Thee are two different things.

Mr. Spekaer: This rule pertains to the admissibility of question. Sub-rule (10) of Rule 46 Reads-

“It shall not ask for information on any matter which is under adjudication by a court a law having jurisdiction in any part of India...”

Ch. Jai Singh Rathi: That is what I want to submit. The question here is: what has the Government replied to have writ? That is not subjudice.

Mr. Speaker: But that is available in the Court.

Ch. Jai Singh: That is not the point. The Point is that they cannot take shelter that this is subjudice.....

Mr. Speaker: The matter is very straightforward. The Chair cannot force a Minister to reply. The ruling was given by me a year ago. A number of supplementary have been asked. The Minister concerned is not prepared to reply. In any case they have said, “This is subjudice and the document is available.....” What is the point in thrashing it more and more?

Now we go to the next question.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहिब, मेरे लेट होने की वजह से मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष: वह तो अब खत्म हो गया।

श्री दया कृष्ण: सर, लेकिन रिवाइव तो हो सकता है.....

.....

Mr. Speaker: Not now, He Should have been here.

सरकारी बैठों की ओर से आवाजें: हम आप को बाहर बता देंगे.....

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, लोक सभा में यही प्रथा है कि जब कोई मैम्बर लेअ हो जाये औ उस का प्रश्न रह जाये तो यदि क्वेश्चन आवर में समय बचे, तो उसकस वह सवाल पूछने की इजाजत दे जाती है। मै आप से यही चाहूंगा कि उन्हें सवाल पूछने की इजाजत दे दी जाये।

Mr. Speaker: I have already given my dcisio. It cannot be allowed. He has lost his opportunity.

Investigation of Underground water of Tube wells

***1145 Sh. Daya Krishan:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) What steps the Government propose to take to investigate the availability of underground water for the tube wells;

(b) The approximate number of tube wells which are to be constructed in the State during the next five years?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur):

(a) Haryana state Minor Irrigation (Tube wells) Corporation has been set up to explore and assess groundwater potential. The Central Ground water Board (Exploratory Tube wells) Corporation has been set up to water Board (Exploratory Tube well Organization) of the Government of India is also doing some exploratory work.

(b) It is proposed to install, 200 tube wells in the state during the next five years. In addition to the above, about 500 tube wells will be installed for augmentation of supplies in W.J.C.

श्री दया कृष्ण: क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि अखबारों में जा बात आयी थी कि जींद और रोहतक के दरमियान अन्डरग्राउन्ड पानी काफी मिला है, क्या यह बात संच है?

श्री रामधारी गौड़: हां जी, यह दरुस्त है।

श्री दया कृष्ण: क्या मंत्री महोदयत बतायेगे कि उस पानी का किस हद तक और कब इस्तेमाल किया जायेगा?

श्री रामधारी गौड़: बहुत जल्दी ही हम वहां ट्यूबवैल वगैरा लगाने का काम शुरू कर देगे। वहां पर 50 ट्यूबवैल लगाने की योजना है.....

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कहां कहां पर शैलों ट्यूबवैल लग सकते है। और कहां कहां डीप ट्यूबवैल लग सकते है?

श्री रामधारी गौड़: यह तो एक्सप्लोरह होने के बाद मालूम होगा कि कहा शैलों ट्यूबवैल लग सकते है और कहा डीपन ट्यूबवैल लग सते है। लेकिन जहां तक दादूपुर से लेकर मूनक तक के एरिया का ताल्लुक है इस मे डीप ट्यूबवैल लगाये जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह: मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इनके महकमे को जानकीर है कि शैलों ट्यूबवैल कहा कहां लग सकते हैं। यदि है ताक कहा कहा?

श्री रामधारी गौड़: हमने मुख्तलिफ जगह पर एक्सप्लारेशन करवायी है। उसमें हमें इन जगहों का पता लगा है अम्बाल जिल मे नारायणगढ़ तहसील में महेन्द्रगढ जिला में कृष्णावती बैल्ट में, गुडगांवा जिला में, बल्लभगढ़, साहबी नदी और पलवल तहसील में, रोहतक जिला मे इज्जर तहसील में, और जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और घग्घर के नीजदीक। इसी तरह से हांसी तहसील में सफीदों के नजदीक और राजस्थान में।

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब पानी सतह ऊंची हो जाती है ,तो एन्टी-वाटरलोगिंग स्टैप के तौर पर शैलों ट्यूबवैल लगाना जरूरी होता है या नहीं? यदि होता है तो वह कहां कहा लगाये जा रहे है।

श्री रामधारी गौड़: इसका जवाब अभी आप को बता दिया है। वैसे मै आप को बता दूं कि शैलों ट्यूबवैल्ज जमुना नहर के साथ साथ लगाये जायेगे।

चौधरी लाल सिंह: मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे कि सरकार का प्रोग्राम है कि वहां 200 ट्यूबवैल्ज लगाये जोयगे, क्या वह प्रोगाम वही रहेगा या इसे बढ़ाया जायेगा?

श्री रामधारी गौड़: यदि पानी ज्यादा मिला तो जरूर बढ़ाया जायेगा। 200 ट्यूबवैल्ज तो आपके पक्के है ही।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदयत बतायेगे कि एक्सप्लोरेशन किस स्टेज पर है?

श्री रामधारी गौड़: बहन जी आप पहले इस लफज के मायने समझ ले।

श्रीमती चन्द्रावती: तो आप मायने भी बतला दीजिए कि एक्सप्लोरेशन क्या होता है?

श्री रामधारी गौड़: मैने यह बताया है कि फला फला जगह पर ट्यूबवैल्ट लगाये जायेगे। एक्सप्लोरेशन होने के बाद ही पता लगता है कि कहां ट्यूबवैल लग सकता है?

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का तो जवाब आया ही नहीं।

श्री रामधारी गौड़: जैसे मैने बताया, एक्सप्लोरेशन होने के बाद ही यह किया है कि कहां कहां ट्यूबवैल्ज लगाये जायेंगे....

.....

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): We have yet to go a very off. This exploration work will take long to complete. This connection, we are carrying out experiments everywhere in the attend trying to find out underground date about the water available that the tube wells can be installed. This research is going on a very ge scale.

Mr. Speaker: The House wanted to know as the how much areas has been covered and how much still remains?

Sh. Bansi Lal: It has not been possible to find out these details far. However, I may state that shallow tub wells are sunk near the where the water level is higher, and deep wells are sunk near the ears Viz., Jamuna, Krishnawait and in some areas of Ghaggar.

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीर: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दादूपरु से जमुना कैनान तक जो ट्यूबवैल ला रहे है। उनका पानी क्या वहां के लोगों को दिया जाएगा जो वहां काश्त करते है या सिर्फ नहर में डाला जाएगा?

श्री रामधारी गौड़: यह आगमेन्टेशन के लिए लगाए जायेगे।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीर: अगर वे लोग मांग करें तो क्या उन लोगों को भी पानी दिया जाएगा?

श्री रामधारी गौड़: उन लोगों के लिए दूसरी किस्म के ट्यूबवैल होंगे तो डारेक्ट होंगे। ये आगमेन्टेशन के है।

श्रीमती लेखवती जैन: मै मंत्री महोदयत से पूछना चाहती हूं कि क्या अम्बाला जिले की अम्बाल तहसील में 1971-72 में सरकार की ट्यूबवैल लगाने की कोई स्कीम है?

श्री रामधारी गौड़: नारायणगढ़ में लगाए जायेगे।

श्रीमती लेखवती जैन: मै अम्बाला तहसली की बाबत पूछ रही हूँ।

श्री रामधारी गौड़: नारायणगढ़ में जब मुकमल हो जायेगे और वहां अगर पानी मिल जाएगा तो वहा भी लगाए जायेगे।

श्रीमती लेखवती जैन: क्या वहा कोई जांच करवाई गई है। कि वहां पानी है या नहीं?

श्री रामधारी गौड़: अम्बाला में जांच हो रही है।

श्रीमती लेखवती जैन: वहां केवल इरीगेशन के पानी की ही कमी नहीं है वहां पीने के पानी की भी बहुत कमी है।

श्री रामधारी गौड़: वहा जो ट्यूबवैल लगाए जायेगे और पानी दिया जाएग वह पानी पिया भी जा सकता है।

श्री सत्य नारायाण सिगांल: मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि दादूपुर से मून तक वैस्टन जमुना कैनाल के साथ साथ शैलों ट्यूबवैल लगाए जायेगे, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपया करेंगे कि मूनक फाल से मुआना फाल जहां कि पानी की बहुत ज्यादाती है वहां पर भी शैलों ट्यूबवैल लगाए जायेगे?

श्री रामधारी गौड़: हां वहां पर भी लगाए जायेगे। वहां मूनक से लेकर खुगडू तक लगायेगे।

श्री सत्य नारायाण सिंगोल: खुगडू तो दूसरी नहीं हुई।
नहीं जमनगर्वी पर मूनक से मुआना तक.....

श्री रामधारी गौड: खुगडू जमनगर्वी पर ही है।

श्री सत्य नारायाण सिंगोल: पंडित जी नहर जमनगर्वी की आगे तीन शाखाएं हैं मैं पूछ रहा हूं कि जमनगर्वी की जो हांसी शाखा है उसके लिए मूनक से मुआना फाल तक जो अंटा फाल और फिर उसके बाद मुआना फाल है वहां तक भी लगायेगे? खुगडू तो दूसरी लाईन है।

श्री रामधारी गौड: वहां भी लगाए जायेगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट आफ आडर है, जीन्द स्टेट के गांव का एक आदमी फौज में भर्ती हो गया। एक बार उसको छुट्टी लेनी थी। उसके 'सूल' शब्द तो याद नहीं रहा वह कहने लगा कि जो इसे हो गया है वही मुझे हो गया है जा बात सिंगोल साहब कर रहे हैं वही बात वजीर साहिब कर रहे हैं। वजीर साहिब को यह ता पता नहीं कि जमनगर्वी वहां नहीं है।

श्री रामधारी गौड: वह हांसी ब्रांच ही जमनगर्वी है।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करकेगे कि अमृतसर में एक इरिगेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट है

जिसने पानी के बारमें एक रिपोर्ट तैयाकर की थी, क्या सरकार के पास उसकी प्रतिलिपियां हैं?

श्री रामधारी गौड: उसकी प्रतिलिपियां मेरे पास नहीं हैं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्टवाइज एक नक्शा बनाया था जिसे पता लगता था कि पानी कहां मीआ है, ट्यूबवैल कहा लग सकता है, कहां पानी खारा है। सफीदो में कुछ एरिया में पानी बहुत मीटा है, मीटे पनी की लेयर कहां तक है इसको जानने के लिए क्या कोई एक्सप्लोरेशन करने का विचार है?

श्री रामधारी गौड: बाद की स्टेज में देखा जाएगा।

चौधरी रणबीर सिंह: मंत्री महोदय ने बताया है कि इरीगेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट अमृतसर की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी कहां ऊंचा है, कहां नीचा है, कहां खारा है। वह बहुत फायदे की चीज है, उस में हमारा भी हिस्सा है। क्या सरकार उसकी प्रतिलिपियां हासिल करने की कोशिश करेगी?

श्री बंसी लाल: कर लेगे

श्री रामधारी गौड: अगर जरूरत हुई तो कर लेगे।

चौधरी रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के जवाब देने के बाद भी यह कहा जा रहा है कि अगर जरूरत हुई तो प्रतिलिपियों हासिल कर लेगे।

श्री बंसी लाल: वह तो दूसरे प्वायंट का जवाब दे रहे हैं।

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करने कि जींद और रोहतक के दरमियान जमीन के नीचे कोई पानी मिला है, वह कब मिला है और कौन से गांव के पास मिला है?

श्री रामधारी गौड: जींद के पास सफीदों का इलाका है, रोहतक का नहीं।

श्री दया कृष्ण: आज सवेरे मैंने अखबार में पढ़ा है कि जींद और रोहतक के दरमियान पानी की अन्डरग्राउन्ट लेयर मिली है।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब ऐसा है कि एक वैल्ट इस किस्म की पूरी स्टेट में से गुजरती है जिस की तीन बैल्टें बनती है। 'ब्रॉडली' इसमें एक बैल्ट का कुछ हिस्सा रोहतक और जींद के बीच में कहीं टच करता है लेकिन उसका एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है। कम्प्लीट इन्फर्मेशन हम इस लिए नहीं दे सकते। अभी वहां थोड़ी ही रिग्ज है और जब ज्यादा रिग्ज आ जायेगी तब हम कम्प्लीट इन्फर्मेशन दे सकेंगे। लेकिन मैं हाउस

को यह यकीन दिला सकता हूं कि जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा हम डीप ट्यूबवैल ओर शैलों ट्यूबवैल लगाते जायेगे। अभी तक उसकी तफतीश पूरी नहीं हुई है। इट इज स्टिंग गोइंग औन।

श्रीमती लेखवती जैन: मैं यह पूछना चाहती हूं कि गवर्नमेंट की ट्यूबवैल लगाने की नीति क्या है। क्या वह ट्यूबवैल उन जिलों और तहसीलों में लगाती है जहां पहले ही है या उन जिलों और तहसीलों को परैफरेन्स दिया जाता है जहां ट्यूबवैल बिल्कुल नहीं है या कम है।

श्री रामधारी गौड: जहां पानी मिल जाता है वही ट्यूबवैल लगाते है। जहां कही मीठा पानी मिल सकता है उन सब जगहों पर ट्यूबवैल लगाए जायेगे।

श्रीमती लेखवती जैन: क्या वजीर साहब बतायेगे कि अम्बाला जिला ही तहसील अम्बाला में भी मीठा पानी मिला है कि नहीं?

श्री रामधारी गौड: अम्बाला जिला का तकरीबन सारा ही इलाका ऐसा है जहां पानी मिला है। इसलिए सारे हील अम्बाला के जिला में ट्यूबवैल लगाए जायेगे।

श्री भगवान दास सहगल: अम्बाला की तहसीलें अभी तक एक भी ट्यूबवैल नहीं लगाया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर कब तक ट्यूबवैल लगाये जायेगे?

श्री रामधारी गौड: जल्दी की कोशिश करेंगे ।

(इस समय खान साहब अपनी सीट पर से उठ कर साथ वाली की सीट पर गए)

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब क्या खान साहिब भी सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते हैं

चौधरी जय सिंह राठी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब पहले तो खान साहिब ने फ्लोर क्रास कर लिया था और फिर दूसरे की सीट पर से बोलने के लिए खड़े हो गए हैं। क्या वह ऐसा कर सकते हैं?

Mr. Speaker: I will request the Minister for Irrigation to please address the Chair and not the Member concerned. If he talks facing that side, the hon. Members sitting on the other side cannot hear and then the trouble arises. Therefore, kindly address the Chair while giving answers to the supplementaries.

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, जैसे सरकार ने हर गांव के अन्दर बिजली और सड़कें बनानी लाजमी कर दी हैं क्या उसी तरीके से सरकार की हरियाणा में हर जमींदार को खेती के लिए पानी देने की स्कीम है?

श्री रामधारी गौड: हां जी है ।

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खान): जनाब स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि खान साहब

सप्लीमैट्री सवाल पूछ सकते है। क नही पूछ सकते है। मै भी जानता था कि मै नही पूछ सकता, मैने अपने कोलीग श्री हरपाल सिंह जी से मश्वरा भी किया था, मै चाहता हूं कि अपने लीगल एडवाईजर से पूछ लूं। उन्होने यह फरमाया कि कुओं के मुताल्लिक पूछ सकते हो। इस लिए यह कहना चाहता हूं कि जहां पर लगा दिए गए है वहा तो लग चुके लेकिन आयंदा लिए यह देखना चाहिए कि जहां पर नही है वहां पर लगाए जाए।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब बतायेगे कि खान साहब की कांस्टिच्यूएंसी में कितने डीप और शैलों ट्यूबवैल लग सकते है।

Mr. Speaker: They have not got that informto jwith them here.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: अभी मंत्री महोदय ने फरमाया था जहां कही भी मीठा पानी होगा वहां ट्यूबवैल लगाए जायेगे। हमारे इलाके में मूनक से मुआना फाल तक नहर की तीन शाखाएं है, एक हांसी ब्रांच है, दूसरी सरसा ब्रांच और तीसरी सुन्दर ब्रांच है वहा पर खुशकी के वक्त बारी बारी पानी दिया जाता है, यानि जब एक में पानी छोडत्रा जाता है तो दूसरी दो सूखी रहती है। वहां पर जमीन के अन्दर सारा पानी मीटा है। क्या वहां पर साथ साथ शैलों ट्यूबवैल लगा कर सरकार उन तीनों नहरों को पानी देने का प्रबन्ध करने के लिए तैयार है?

श्री रामधारी गौड: जहां कही भी अच्छा मीठा पानी होगा उसको इरीगेशन की योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। हम वहां पर जांच करवा लेगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: यह बात इन्होंने पिछली बार भी कही थी वहां पर जांच करना लेगे लेकिन अभी तक इन्होंने उस इलाके को दिखलवाया नहीं। मैं वहां का रहने वाला हूं और मैं इनको बता रहा हूँ कि वहां पर जमीन के नीचे इतना मीठा पानी है कि अगर वहां पर उन नहरों के साथ साथ ट्यूबवैल लगा दिए जाएं तो तीन नहरों को फीड किया जा सकता है।

श्री रामधारी गौड: इतना पानी अगर वहां पर है तो उस का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जहां पर नहरों का पानी लगता है और जमीन का पानी मीठा है लेकिन गहरा है वहां पर सरकार ट्यूबवैल लगवा कर किसानों को इरीगेशन के लिए पानी देने का प्रबन्ध करेगी।

श्री रामधारी गौड: हा जी करेगे।

Mr. Speaker: Next question please.

Ch. Jai Singh Rathi: Question No. 1157, Sir.

Mr. Spekaer: I have granted extension for this question. Next question please.

Reported case of Embezzlement in Yamunangar

***1184. Dr. Malik Chand Gambir:** Will the Minister of Development be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that there has been a case of embezzlement involving Rs. 1 ½ lakhs in the Yamunangar Co-operative Consumer store, since 1st January, 1970;

(b) Whether any enquiry has been instituted in the said case; if so, the results thereof; and

(c) Whether any person has been held responsible in this connection?

Development Minister (Sh. Sarupb Singh): (a) No. Sir,

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

डाक्टर मलिक चन्द्र गम्भीर: क्या वजीर साहिब तायेगे कि वहां पर कोआरेटिव कंज्यूमर स्टोरे की तरफ से कोई इंकवायरी हुई थी?

श्री सरूप सिंह: हां जी उन्होंने एक कमेटी कुरर करके इंकवायरी करवाई थी।

डाक्टर मलिक चन्द्र गम्भीर: क्या वजीर साहिब तायेगे कि उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री सरूप सिंह: उनकी रिपोर्ट यह है कि जो वाईस-प्रेसीडेंट श्री भजन लाल था वह उसका जिम्मेवाद है।

डाक्टर मलिक चन्द्र गम्भीर: क्या वजीर साहिब बताएंगे कि उसके बारद क्या इक्दामात उठाए गए है?

श्री सरूप सिंह: उसके बाद कोआपरेटिव के इन्स्पैक्टर ने इन्क्वायरी की थी और उसकी भी सही रिपोर्ट है कि वही आदमी जिम्मेवार है। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाईटीज अम्बाला के पास इन्क्वायरी है जो कि अभी तक पैडिंग है।

डाक्टर मलि चन्द गम्भीर: जब दो दफा इन्क्वायरी मे एक आदमी दोषी ठहराया गया है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

श्री सरूप सिंह: कोआपरेटि एक्ट के सैक्शन 54 क कतहत एक्शन लिया जा रहा है।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मै जान कसता हूं कि यह डेढ़ लाख का घाटा कितने अर्से का है और कब इसके बारमे जानकारी मिली?

श्री सरूप सिंह: इस के मुताल्लिक मैने जवाब दिया है डेढ़ लाख का घाटा नहीं हुआ और न ही उसकी इन्क्वायरी हुई है।

चौधरी रणबीर सिंह: लास तो घाटे को ही कते है, मै यह जानना चाहता हूं कि कितना लास हुआ और कब से वह

गवर्नमेंट।अ क नोटिस में आया है।र क्या महकमें ने एकोई एक्शन लिया?

श्री सरूप सिंह: कंज्यूमर स्टोर यमुनानगर ने 24.8.69 को एक सब कमेंटी मुकर्रर की थी और उसने 4.11.70 को अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद इंस्पैक्टर कोआपरेटिव सोसाईटीज ने इन्क्वायरी की और घाटा 30 जून, 1970 तक 16 हजार 30 रूपए 90 पैसे का था।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीर: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या वह वाइए चेयरमैन आजकल भी कोई आफिस होल्ड करता है वहां पर?

श्री सरूप सिंह: इसके लिए सैपरेट नोटिस दे तो पता करके बता देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि सब कमेंटी के रिपोर्ट आने से पहले या सब कमेंटी बनने से पहले अडिटन ने इस घाटे के बारे में रिपोर्ट की और अगर की तो कब की और किस साल के बारमें में की?

श्री सरूप सिंह: आडिट रिपोर्ट इस बारे में आई कि स्टाफ की कमी हुई और 16,996 रूपए और 70 पैसे की मिसएप्प्रपरिएशन की गई और उस बारमें में उन एम्पालाईज के बारमें में रिकवारी के लिए एक्शन लिया जा रहा है।

चौधरी रणबीर सिंह: मंत्री महोदय दो बातें तो अभी मान गये हैं और वह यह कि यह मिसएप्रोपरियशन हुई और दूसरे यह कि 16 हजार और कुछरूपए का घाटा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह चीज पहले आडिटर ने बताई कि ऐसा हुआ है कि या और किसी तरह से इस बारे में पता चला था और क्या आडिट हुआ या नहीं और हुआ तो उसने यह बताया और अगर नहीं बताया तो क्या उसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है या नहीं?

श्री सरूप सिंह: सब कमेटी जो बनी थी उसने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया गया इस बारे में।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मैं जान सककता हूँ कि यह घाटा सारा एक ही साल का है जिस साल रिपोर्ट हुई या उससे पहले का भी है?

श्री सरूप सिंह: वह पिछले सालों का है। जिसके बारमें में अभी इन्क्वायरी पैडिंग है।

चौधरी रणबीर सिंह: उस साल से पहले के बारमें घाटा की बात है तो मतलब जानना चाहता हूँ कि आडिटर ने रिपोर्ट कब की, उसके बाद क्या कार्यवाही हुई और किस किस साल में बारमें में घाटा है?

श्री सरूप सिंह: आडिट रिपोर्ट 1969-70 की है।

चौधरी रणबीर सिंह: मैंने तो यह पूछा है कि नौसे साल की आडिट रिपोर्ट में इनस्पैक्टर ने बताया कि सोसायटी को घाटा है और उसके बाद महकमा ने इस बारे में क्या कार्यवाही की?

श्री सरूप सिंह: सब कमेटी जो मुकर्रर की थी सब से पहले उसने घाटा प्यावयंट आउट किया और अब यह सारा केस ए० आर० के पास पैडिंग एक्शन है।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मैं जान सकता हूँ कि सब कमेटी बनाने से पहले क्या इन इनस्पैक्टर ने घाटे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और अगर नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं जिन्होंने नहीं बताया कि घाटा है?

श्री सरूप सिंह: घाटा नफा तो बोर्ड होता है वह खु ही देखता है जिस तरह स्टोर्ज में भी जोता है। लास की रिपोर्ट नहीं आई मिसएप्रोपरिऐशन की है लास का मतलब यह है कि कुछ चीजे ऐसी खरीदी गई जो बिक्री में नहीं आई।

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहिब बतायेगे कि इतने बड़े घाटा का बजूहात क्या है?

श्री सरूप सिंह: यह सारा केस अभी ए०आर० के पास है उससे अभी रिपोर्ट नहीं आई। आने पर पता लगेगा।

चौधरी जय सिंह राठी: क्या वजीर साहिब तायेगे कि जो पहले इंकवायरीज हुई हैं और रिपोर्ट्स आई उन में बताया गया है कि रीजनल थे?

श्री सरूप सिंह: यह सारा केस अभी मैंने अर्ज किया ए०आर० के पास पड़ा है और उसकी रिपोर्ट आने पर सारा पता लगेगा।

चौधरी जय सिंह राठी: मैंने यह पूछा है कि उन रिपोर्ट्स में क्या रीजनल दिये गये थे इस लास के?

श्री सरूप सिंह: इस में बात यह है कि सब कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि वाइस चेयरमैन जिम्मेदार है। और इनस्पैक्टर ने लिखा है कि उसमें से कुछ रकम के लिए वाइस चेयरमैन जिम्मेदार हैं इसलिए यह सारा मामला ए.आर. के सपुर्द किया गया है कि वह देखे कौन कितना जिम्मेदार है और क्या एक्शन हो सकता है।

चौधरी जय सिंह राठी: क्या यह सही है कि इतने बड़े लास का रीजनल यही था कि उनकी जाती जिम्मेदारी है या और कोई रीजनल दिया गया है?

श्री सरूप सिंह: मैंने अर्ज किया है कि अभी ए.आर. की रिपोर्ट नहीं आई है और उसे आने पर सारा पता लगेगा कि क्या कोई एक जिम्मेदार है या सारे मैम्बर जिम्मेदार हैं और उसके बाद एक्शन होगा।

डाक्टर रामेश्वर दास गुप्ता: क्या वजीर साहब बतायेगे कि उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोआपरेटिव स्टोर की दुकाने खरीदने के बरमें मे एम्बैजलमेंट की गई है।?

श्री सरूप सिंह: इनस्पैक्टर ने लास के बरमें बताया कि इनत है। सब इनस्पैक्टर और सक कमेटी की मिल गई इसलिए ए. आर. से कहा गयाकि वह देखे कि क्या बात है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मैं जान सकती हूँकि जिन लोगों को दोषी पाया गया और जिम्मेदार ठहरयाया गया वह अभी उस सोसायटी में आफिस होल्ट कर रहे है?

श्री सरूप सिंह: अभी रिपोर्ट इस बारें मे मुकम्मल नही आई रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जायेगा।

चौधरी जय सिंह राठी: वजीर साहिब ने शु में बताया था कि इनस्पैक्टर ने जिन के खिलाफ रिपोर्ट दी थी उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह किस कानून की बिना पर की गई है?

श्री सरूप सिंह: सरचार्ज की प्रोसीडिंगज अलग से चलेगी और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ अलग से एक्शन लिया जायेगा। रिपोर्ट आने पर अब हमने ए.आर. से कहा है कि वह देखे कि कौन जिम्मेदार है ओर कितना जिम्मेदार है?

चौधरी जय सिंह राठी: क्या अब तक उन आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

श्री सरूप सिंह: जहां तक मिसएप्रोपियरेशन का सम्बन्ध है उनके खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही चालू है। ओर सरचार्ज की प्रोसीडिंगज चालू है।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि वह सालाना बैनेन्स की रिपोर्ट हर साल बनाते थे यह नहीं और क्या उस रिपोर्ट की कापी ए.आर. या महकमा के अफसरों के पास आती थी या नहीं और क्या उनमें खिसारा दिखाया गया था या नहीं?

श्री सरूप सिंह: यह इनफर्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

डाक्टर रामेशवर दास गुप्ता: मैं जानता चाहता हूं कि जो सब कमेटी बनी थी जिस की रिपोर्ट का यहां जिकर आया है उसकी सारी फाईडिंगज आडिट रिपोर्ट के बारे में है और क्या पहले जो आडिट रिपोर्ट्स आया करती थी उनमें घाटा वगैरहा दिखाते रहे हैं या नहीं?

श्री सरूप सिंह: इस सवाल का जवाब पहले दिया जा चुका है। शुरू में जो सब कमेटी मुकर्रर की थी उसकी रिपोर्ट आइ थी फि फला आदमी जिम्मेदार है इस रिपोर्ट पर एक इन्सपैक्टर को इन्क्वायरी के लिए लगाया था जिसकी रिपोर्ट को आपरेटिव रजिस्ट्रार के पास इन्क्वायरी के लिए पैडिंग है।

श्री सत्य नारायाण सिंगोल: स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल कोआपरेटि कंज्यूमर्ज स्टोर यमुनानगर के बारे में है। लेकिन इस किस्म की सोसाइटियों कई जगहों पर कै जिन में गबन और कुरप्शन हुई है आर उनकी इन्क्वायरीज दो तीन सालों से चल रही है। क्या सरकार उन केसिज को फाईनेलाईज करने के लिए कोई कार्य वाही करेगी?

श्री सरूप सिंह: जो भी शिकायत होगी उस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। जो पुराने केसिज है उनको फाईनेलाईज जल्दी ही किया जाएगा।

Mr. Speaker: Net question, Sh. Ranbir Singh.

Sh. Satya Narain Syngol: What about the St. Question No. 1146 by Sh. Daya Krishan?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which I have allowed.

New High Schools for Girsl

*1158 Sh. Ranbir Singh: Will the Minister for E\ducation be pleased to state the total number for Government Girls High Schools opened in Haryana in 1970?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Seven by upgrading the existing Middle schols.

चौधरी जय सिंह राठी: क्या मिनिस्टर महोदय बतायेगे कि ये स्कूल किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस किस जगह हैं?

श्री माड सिंह मलिक: ये सांपला जिला रोहतक, चांग जिला हिसार नगीना जिला, गुडगांव, हथीन जिला गुडगांव, कैम्प पलवल जिला गुडगांव, नेयतपुर जिला महेन्द्रगढ़, बोडकला जिला महेन्द्रगढ़ में है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदयत बतायेगे कि जो स्कूल इन्होंने खोले है इन में कितनी फीसदी लड़कियों पढ़ेगी?

श्री माडू सिंह मलिक: ये तो लड़कियों के स्कूल है और लड़कियां ही पढ़ेगी। (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: मेरा मतलब है इन स्कूलों में कितनी परसेंट पढ़ेगी? कितनी लड़कियों को फायदा पहुंचेगा? आप सवालों को ऐसे ही टाल देते है जवाब देना ही नहीं आता।

श्री माडू सिंह मलिक: हमने स्कूल खोल दिए है और आगे उनके मां बा पर निर्भर करता है कि वे कितनी लड़कियों को स्कूल में भेजते हैं

श्री दया कृष्ण: वजीर साहिब ने सात स्कूलों के बारे में बताया है कि फलां फलां जगह खोले है। यह सब जानते है कि हरियाणा लड़कियों की तालीम में पिछड़ा हुआ और जिला जींद से

सबस ज्यादा पिछडा हुआ है क्या वजीर साहिब जींद जैसे पिछडे हुए इलाके में लड़कियों के स्कूल खोलेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: हम 50 फीसदी लड़कियों के और 50 फीसदी लड़कों के स्कूल अपग्रेड करेंगे।

चौधरी जय सिंह राठी: क्या वजीर साहिब बतायेगे कि जिस जगह से स्कूल अपग्रेड करेंगे, क्या सरकार उस जगह की आदि को सीडर नहीं करती? क्या यह न देखा जाता कि इन स्कूल में कितनी बच्चे पढ़ेंगे, क्या यह हाई स्कूल चल भी सकता है या नहीं, इन बातों को कंसीडर किया जाता है या नहीं?

श्री माडू सिंह मलिक: जी हा, कंसीडर किया जाता है।

चौधरी जय सिंह राठी: अगर कंसीडर किया जात है तो क्या वजीर साहिब बतायेगे कि इन सात स्कूलों में किस किस स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। और कितनी आबादी है?

श्री माडू सिंह मलिक: ये स्कूल लड़कियों के लिए हैं। जितनी लड़कियों को उनके मां बाप भेजेगे उतने पढोगे।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहिब, पिछले दिनों वजीर साहिब सिढौरा गये थे, वहा लड़कियों का स्कूल नहीं है और बहुत ज्यादा आबादी है। क्या वहा स्कूल खोलने लिए आर्डर जारी कर दिए गए हैं।

श्री माडू सिंह मलिक: जिस स्कूल की बिल्डर तैयार हो जाएगी आर्डर जारी कर देगे ।

चौधरी जय सिंह राठी: क्या वजीर साहिब बतायेगे कि तहसील पानीपत के तीन गावों में जहां कि बिल्डिंगज बनी हुई है और स्टूडेंट्स भी है और उनके मंत्री महोदय के पास आये थे कि वहां पर स्कूल खो दो लेकिन मंत्री महोदय ने वहा स्कूल खोने से इन्कार कर दिया, क्या यह ठीक है?

श्री माडू सिंह मलिक: बिल्कुल गलत है ।

चौधरी जय सिंह राठी: क्या सरकार अब खोलने के लिए तैयार है?

श्री माडू सिंह मलिक: जो सरकारी कंडीशन्ज है, अगर वे पूरी हो जायेगी तो स्कूल खोल देगे ।

चौधरी लाल सिंह: क्या मिनिस्टर महोदय बतायेगे जैसा उनहोने कहा कि 20 हजार रूपया दे दो तो हम बिल्डिंग बनसा देग.....

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): ऐसा तो नही कहा था ।

श्री सत्य नारायाण सिंगोल: जो स्कूल आपने खोले है क्या इनकी सारी कंडीशन्ज पूरी हो गई है?

श्री माडू सिंह मलिक: जी हां

श्री सत्य नारायाण सिंगोल: जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि 50 फीसदी लड़कियों और लड़कों के स्कूल अपग्रेड करेंगे। मैं अपने गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वहां तो अपग्रेडेशन हो नहीं सकती। दो गांव हैं— काटवा और हाल। क्या इन गावों के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: अगर वे कंडीशनज पूरी करते होंगे तो जरूर कर देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर कंडीशनज पूरी होगी तो मिडल स्कूल से हाई स्कूल अपग्रेड कर दिया जाएगा। वे क्या कंडीशनज हैं, क्या क्राइटीरिया हैं जिसके बेसिज पर स्कूल अपग्रेड होंगे?

Sh. Maru Singh Malik: The Government have prescribed the following condition for upgrading a Government Middle School to High Standard:-

(i) There is a demand for upgrading a school from the local community;

(ii) The enrolment in a school justifies it upgrading;

(iii) The local community is prepared to construct or has already school;

(iv) The back/flood-affected areas are generally given preference while upgrading schools; and

(v) (a) Building accommodation	15 rooms
(b) Land	8 acres (Including playground)
(c) Enrolment	300 (Average attendance during the last six months)
(d) Distance from the nearest Middle/ High Higher Secondary School	5 miles
(e) Population	2,000 or above.
(f) Staff Quarters	20 (in phased manner)

Mr. Speaker: Questio Hour is over.

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advissry Committee in regard to various business.

The Committee met at 10-00 A.M. on 12th February, 1971

After some discussion, the Committee recommended that the following revised programmed of business be observed from 12 the February, 1971 (II Sitting) onwards:-

1. On the 12the February, 1971, the Assembly shall, in its second sitting at 2-00 P.M. transact the following Business:-

2. Second Report of the Business advisory committee.

4. Appropriation Bill in respect of supplementary estimates (2nd Installment) 1970-71

5. Legislative Business.

(Time to be extended, if necessary.)

(13th February, 1971: off day)

(14th February, 1971: Holiday)

2. On the 15th February, 1971, the assembly shall meet at 2-00 P.M. and transact the following business:-

1. Question hour.

2. Discussion on Budget Estimates for the year 1971-72.

(Time to be extended, if necessary)

3. On 16th February, 1971, there shall be two sittings and the business be transacted as follows:-

1st sitting (9-30 A.M.)

1. Question hour.

2. Discussion and voting on demands for Grants on Budget Estimates for the year 1971-72

2nd Sitting (2-00 P.M)

1. Appropriation Bill in respect of the Budget Estimates for the year 1971-72

2. Legislative Business.

3. Discussion on—

(a) The annual report on the working of the Hayrana Public Service Commission (1st April, 1969 to 31st March, 1971).

(b) The annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71.

(Time to be extended, if necessary)

Industries Minister (Sh. Abdul Ghaffar Khan): Sir, I bet to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this house agrees with the recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर सहिब, यह कनैश्चन बिल्कुल इल्लीगल हे ।

Mr. Speaker: Now, the question has been put.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मै तो उसी वक्त खड़ा हो गया था परन्तु आपेन जल्दी से ही क्वैश्चन पुट कर दिया ।

Mr. Speaker: This has been done unanimously by the Business advisory Committee.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: स्पीकर सहिब, रूल 39 बिल्कुल क्लीयर है इसके मुताबिक जिस तरह से यहां प्रोसीजर अडोप्ट किया गया है वह नही किया जाना चाहिए था भले ही फ़ैसला चुनानिमसी हुआ हो फिर भी This cannot be doen tlie that.

Mr. Speaker: I think, you are too late. You should have brought up the matter earlier.

श्री सत्य नाराण सिंगोल: स्पीकर साहब, मै कहता तो तब अगर मुझे टाईम मिलता। दसरे इसे तो लीडर आफ दी हाउस को मूव करना चाहिए था।

Mr. Speaker: According to the rules, any member of the committee can move in motion.

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Rule No. 37 is quite clear. It lays down:

“As soon as may be after the report has been made to the House a motion may be moved by a member of the Committee.....”

So, any member can move the motion.

Sh. Satya Narain Syngol: It does not means that the prescribed procedure should be over ruled, because Rules 39 says:

“No variation in the allocation of the time order shall be made except on the request of the Leader of the Hose who shall notify orally to the House that there is general I agreement for such variation.....”

Sh. Om Prabha Jain: It does not involve any variation of the business.

Mr. Speaker: I am afraid, the question has now been put. I wish, this should have been brought to my notice earlier. In any case, this was the unanimous decision of the Business advisory committee.

Sh. Sarna Narain Syngol: After the general agreement an oral request has to be made by the Leader of the House and not by any body else.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): It was on my request that the business advisory committee took the decision about the allocation of the business.

Mr. Speaker: I will not put the question again. Question is-

That this House agrees with recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

The Motion was carried.

PRESENTATION OF REPORTS

Chairman, Public Accounts Committee (Sh. Raj Singh Dalal): Sir, I beg to present the Third report of the public account committee (1970-71) on the appropriation accounts of the Haryana government for the years 1966-67 and 1967-68 and the audit reports, 1968 and 1969.

Chairman, Estimates committee (Sh. Chandravati): Sir, I beg to present the third Report the estimates committee (1970-71) on the budget estimates for the year 1970-71.

Chairman, Committee on subordinate Legislation (Ch. Chand Ram): Sir, I beg to present the third report of the committee on subordinate legislation (1970-71).

Sh. Kanwar Singh Dahiya (A member of the Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the third Report of the Government on the Government Assurances (1970-71).

LIGSLATIVE BUSINESS.

THE HARYANA APPROPRIATION BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Sir, I bet to introduce the Haryana Appropriation Bill.

Sir, I also bet to move-

That the Haryana Appropriation bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana appropriation bill taken into consideration at once.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Since nobody wants to speak, I shall put the question to the vote of the House.

Ch. Jai Singh Rathi (Naultha): I want to speak, Sir, I was just collecting my papers.

स्पीकर साहिब, ऐप्रोप्रिएशन बिल हाउस के सामने आया है हरियाणा पर खर्चे की भी बात है, पैसे की भी बात है और हमारे फाईनैन्सिज की भी बात है। (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन

हुई) डिप्टी स्पीकर सहिबा, यही सरकार जो आज ऐप्रोप्रिएशन बिल लाई है बड़े तमतारक सक कहती है कि ख्वाह अपोजीशन के मैमबरकुछ भी कहत रहे, जो मर्जी क्रिटिसिज्म करते रहे, चाहे सड़कों के बारमें करें, बिजली के बारें मे याऔर किसी चीज के बारें में करें उसे हम नही मानते क्योंकि ये उसे जल कर करते है। क्योंकि हम तो कर रहे तरक्की औरवह तरक्की इन्हे भाती नही। ऐसा कार तो मेरे ख्याल में अपोजीशन के किसी मैम्बर ने नही किया कि कोई अच्छा स्टैप हो और उसे भी उसेन क्रिटिलाईज किया हो। डिप्टी स्पीकर साहिब, कल जो चीफ मिनिस्टर साबि यह दावा कर रहे थे कि हमें कही रास्ता नही मिलेगा, सब दरवाजे हमारे लिये बंद हो जायेगे क्योंकि वे काम कर रहे है उसके बारमें मेरी अर्ज है कि इन्होने क्या काम कियाहै इसको जनता देख लेगी। सरदार प्रातप सिंह कैरों भी इसी तरह से चले थे। कोई भी काम अपनने हल्के उसने नही छोड़ा था। बिजली, सड़क, पटवारी, मास्टर, जा कुछभी था सबा का बस उसने अपने हल्के में पहुंचा दियाथा लेकिन झूठी 33 वोटो से जीत कर आए थे लोगोन ने पीट पीटप रक भूत बना दिया था।

श्री बनारसी दास गुप्ता: वे और भी कुछ करते थे।

चौधरी जय सिंह राठी: वही तो मै कहने जा रहा हूं कि लोग तुम्हझरे हम काम को देखेगे। बेईमानी कितनी की है उसे भी ढूंढ लेगे। ये जिन जिन कामों का बहाना करना चाहते है उनकी तह में कितनी बेईमानी है उसे भी देखेगे। सड़कों की चौड़ाई और

मोटाई को अवश्य देखेगी इधर से कितने बढ़े है उधर से कितने घटे है वह सब कुद देख लेगी।

(श्री बनारसी दास गुप्ता की तरफ से विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर सहिबा, मैं आपसे सबमिशन करूंगा कि अगर ये इस तरह से बीच में ने टोके तो अच्छा रहेगा।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: नहीं नहीं यार चलने दे इनका इलाज मेरे पास है।

श्री बनारसी दास गुप्त: अगर तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगती है तो मैं चला जाता हूँ। (श्री बनारसी दास जी उठ कर बाहर चले गए।)

श्री सत्यनाराण सिंगोल: नहीं नहीं, आप बैठे।

चौधरी जय सिंह राठी: वह बैठे कैसे? उसकी आंखों में तो हिम्मत नहीं कि वह मुझ से आंखे मिलाकर बात कर सके।

डिप्टी स्पीकर सहिब, मैं आन से सबमिशन कर रहा था। ट्रैयुरी बैचिज की हर बात को हम बड़ी खामोशी के साथ सुनते हैं इसलिइनको भी चाहिए कि हमारी हर बात का ध्यान से सुन और उसमें अगर कोई बात इन्हे गलत लगे तो इनमें से कोई सदस्य अगर लिखा पढ़ा यहां पबैठा है उसे नोट कर ले और बाद में जवाब दे दिया करे।(हंसी) तो, डिप्टी स्पीकर सहिब, मैं क रहा

था कि जनता सबसे से पहले यह चीज देखती है कि जो पैसा हम टैक्स की सूरत में, रैवन्यू की सूरत में और दूसरे किसी और तरीके से जैसे स्माल सेविंग्स के जरिए या किसी और ढंग से इक्वटा करके सरकार को देते हैं उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही, जनता इस बात को देखती है। यह बड़े तमतराक से कहते हैं। कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है, हम सड़के बना रहे हैं, बिजली के खम्भे लगा दिए, यह पहुंचा दिया और वह पहुंचा दिया लेकिन मैं इन्हे बताना चाहता हूँ कि ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। यह इनकी ड्यूटी है। अगर इन्होंने ये काम नहीं करने हैं तो ये जो अफसर साहिबान यहां बैठे हैं ये किसलिए बैठे हैं? लोग रैवन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, स्माल सेविंग्स के जरिए कुलैक्शन करके देते हैं। लोग तो एक चीज को चाहते हैं, अगर सरकार उस चीज का कर देती है तो वे इसके सामने सिर झुकाते और हम भी यही कहते हैं कि स्टेट में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कि ला एण्ड आर्डर के थ्रू या अफसरों के थ्रू लोगों के मोरेल को, स्टैंडर्ड को ऊंचा किया अपने देश प्रदेश के प्रति अच्छी भावना पैदा की है परन्तु यह सरकारकेवल अपने मतलब के लिए जातिपाती की बिना पर लोगों को लड़ाती है। अगर दो भाई लड़ते हैं तो उनमें से एक की मदद कर उन का आपस में झगड़ा करवाती हैं अगर सरकार उस पैसे को जो लोगों ने इस को दिया हहुआ है उसको ईमानदारी के साथ खर्च करती तो लोग समझते कि ईमानदारी से काम किया है परन्तु सारी स्टेट के अन्दर मौरल

नाम की तो कोई चीज इस सरकार ने छोड़ी ही नहीं है औनैस्टी, सिनसियेरेटी और टरूथफुलनेस ये चीजे जो इन्सान के अन्दर होनी चाहिए उनका आज नामों—निशान नहीं मिलता है और खासतौर पर उन लोगों के अन्दर जो यह कहते है कि हमने देश की सेवा की है। क्या इन्ही लोगों की सेवा करने वाला कहा जाता है? जैसा कि शोर है—

क्यां कुछ और कहता है निहां कुछ और कहता है।

नजर कुछ और कहती है, जबान कुछ और कहती है।।

बनी बैठी है देखो देश की लीडर।

यहां कुछ और कहती है वहां कुछ और कहती है।।

कहने का मतलब यह है कि जबान और नजर में और है और दिल में कुछ और ही है— और इन के बाहर कुछ और है मैं तो यह कहूंगा कि जिस तरीका से चल रहे है इन पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। लोकगों की पब्लिक लाइफ को इतना गन्दा बना दिया है जिसके विषय में कुछ ब्यान ही नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर साबि यहां तमताराक से कहने लग जाते है। कि सरकार के खिलाफ इन अपोजीशन के भाईयों के पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं, वैसे ही सरकार को क्रिटिसाइज करते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर इनकी मुराद या मकसद हमारे लिए कानून और कंस्टिच्यूशन की बात करन को है उसके लिए तो मैं समझता हूं कि इनके पास अफसर है, चीफ सैक्रटरी, सैक्रेटरी,

डिप्टी सैक्रेटरी और ज्वायंट सैक्रेटरी है जो सरकार के काम को चलाते हैं। उनके बारमें मे कहने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन अगर मिनिस्टर साहब भी अपने आप को सरकार में शामिल करते हैं तो मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि इन से स्टेट को बचाये। इनसे तो स्टेट का कोई भी काम नहीं होगा।

डिप्टी स्पीकर साहिब, शायद एक बात को ये भूज जाते हैं कि जब सन् 1968 मे चुनाव हुए थे तो उससे पहले यहां हरियाणा स्टेट के अफ्ठर गवर्नर रूल था। सरकार तो उस वक्त भी यहां कायम थी और वह सरकार चल भी रही थी तथा हरियाणा के हित के काम की कर रही थे। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कुछ भी काम शुरू हुए हैं ये उसी वक्त के किये हुए हैं उसी समय की योजनाये बनायी हुई है। उन्होंने ही सारी योजनाओं के लिए लिखा पढ़ी की हुई थीं इनका तो वही हिसाब है कि माल चोरी करके ता केठ भी जाये और दाग लगे कटडे के मुंह पर। यह तो खामख्वाह की भलाई लेना चाहते हैं इसी सिलसिले में मुठ कए किस्सा भी याद आ गया हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा थोडे ही समय में समाप्त करता हूं दो गावों की आपस में लड़ाई हो गई। उनका असूल थाकि शामो जब लड़ाई खत्म हो जाती तो वे इक्ठे बैठ कर बातचीत करते थे और आमने सामने बैठ कर ही खाना पीनक करते थे। दोनों पार्टियों के असूल था शाम को आपस में पूछते थे कि आपका कौन आदमी मारा गया ओर कौन घायल हो गया। एक दिन एक आदमी का पता नहीं

चला, काफी पूछताछ भी की वह आदमी जिन्दा है या मर गया। उसका जिक्र ही चल रहा था कि इतने में वह आ गया उससे पूछा गया कि आपने किसको मारा? उसने कहा कि मैंने किसी को काटा, किसी का पेट काटा, किसी का हाथ लेकिन वहां पर किसी की गर्दन नजर नहीं आयी वरना मैं उसको भी काट देता। कहने का मतलब यह है जब हमने पूछ ये सारी स्कीमें कहां असे आई और किसने बनाई तो उसके बारे में ये कहने को कुछ भी तैयार नहीं। स्कीमें ने इस सरकार से पहले की बनी हुई थी। इन्होंने तो जनता ही यिका है कि इनको इम्पलमेंट करवा दिया, वह भी इस कारण से कि इनको अफसर काबिल मिल गये। उन काबिल अफसरों के कारण यह सारा कम हो गया वरना इनकी काबलियत से हरियणा में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती थी। जनता को तो इनके किसी भी बात की कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमारे पास कोई चीज कहने को नहीं है तो वह अफसरों के खिलाफ नहीं हैं अगर वजीर साहिबान के खिलाफ कहने की बात आये और उनको जो काम करने का तरीका है उससे तो जनता की भलाई नहीं हो सकती।

डिप्टी स्पीकर साहिब, ओर इलजामात को तो मैं नहीं दोहराऊंगा लेकिन कुरप्शन के विषय में तो थोड़ा कहूंगा। आपको पता ही है कि पिछले दो सालों से कितनी कुरप्शन बढ़ गई है। इस सरकार ने नये नये तरीके निकाले हुए हैं, कई तो इनके प्रिविलेजिज बन गये हैं। इस सरकार ने नये नये तरीके निकाले हुए

है, कई तो इनके प्रिविलेजिज बन गये हैं इनके अलग अलग तरीके हैं उस विषय में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वह बहुत लम्बा सब्जेक्ट है लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन्हीं वजीरों के बारे में यहां हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट में एक केस चला। एक व्यक्ति तने जिसका नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा है जो लुहानी का रहने वाला है, उसने हाई कोर्ट में रिट दायर की कि मैं ब्लाक समिति का चेयरमैन हूं। मैं इन्क्वेशन के अन्दर जीता हूं लेकिन मेरा इलैक्शन काफी दिनों से गजट नहीं किया गया है। उस केस में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेसापौडैट बनाये गये थे। वह रिट श्री ओम प्रकाश के हक में हो गई। हाई कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि इनका खर्चा 250 रूपये रेसपौडैट पर डाला जाता है। मुझे तो हैरानी होती है कि सरकार उसका ऐप्रोप्रिएशन बिल में और सप्लिमेंटरी ऐस्टिमेंट में ले आई हैं इसमें सीरियस बात यह है कि यह प्राइवेटली खर्चा हुआ था और वह रेसापौडैट को लगना चाहिए था, क्योंकि इसमें चीफ मिनिस्टर साहब की जाती हार भी थी और दूसरे सरकार की भी हार थीं बड़े दुःख की बात है कि एक आदमी को इन्साफ न दिया जाये, उसे नाम की गजट नोटिफिकेशन न की जाये और जो 250 रूपये कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर साहिब के जिम्मे लगाया था उसको ये सरकार पर डाल रहे हैं। यह तो रेसपौडैट को देना चाहिए था। यह बड़ा सीरियस मामला है। सरकार की आमदनी का एक पैसा भी जयाया हो तो उसका भी हिसाब किबात रखा जाता है। परन्तु यहां तो कई रूप्यों का सवाल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस ओर गौर करे वरना ऐसी रिकवरी

कल को भी हो सकती है। अगर यही तरका अडौप्ट कर लिया जये कि हर मिनिस्टर या आज का चीफ मिनिस्टर यो करें तो हरियाणा की ऐ ऐसी स्टेट है जिसमे मैक्सिमस रिटे है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतनी रिटे हाई कोर्ट में जितनी कि कैरों साहब के वक्त मैं भी नहीं थीं इतना ही नहीं कई रिटों मे अपहोल्ड किया गया है कि चीफ मिनिस्टर ने जो ब्यान दिया है वह गलत है। जब ऐसा फैसला आ गया तो तो इन को चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए लेकिन फिर भी ये सता हथियाये बैठे है। हाई कोर्ट के हुक्म को तो इतना एहताराम होता है कि जब उस का हुक्म हो जाता है तो उसको तबदील करने की कोशिश नहीं क जाती। ये लोग यहां हाउस में खड़े हो कर हमारे नेता अर्थात पं० भगवत दयाल जी को क्रिटिसाइज करते है कि कांग्रेस 'ओ' के नेता ने स्टेट की तरक्की को रो दिया था लेकिन इनके नेताओं ने क्या किया और देश को क्या दिया? यह हम सब जानते है और उस का असर हमारे इस ऐप्रोप्रिशन बिल पर भी पड़ा है। आप यह ने समझे कि मैं आट आफ कांटैक्सट बोल रहा हूं क्योंकि इसी ऐप्रोप्रिएशन बिल में इस बात का रैफ्रन्स है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हू। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके जरिए मतै होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि बीच में बोलना अच्छर नहीं है। वह हाउस के लिए भी अच्छा नहीं और मुझ को बीच में टोकना भी अच्छा नहीं है।

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर इस भाई को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है तो मैं बाहर चला जाता हूँ मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो जरा सा मुस्करा दूँ तो भी ये महसूस करते हैं अगर ये कहें तो मैं उठ कर चला जात हूँ

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे नइकी शैस से कोई वास्ता नहीं है। अब ऐसी शक्ले देखने की मोरी आदत नहीं रही। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने तो इनसे सबक सीखना है। हम नये मैम्बर है। जैसा सबक इनके पास है वह तो मैं सीखने की कोशिश नहीं करूंगा।

श्री के.एल.पोसवाल: जिस शक्लों को आप देखने के आदि है वे देख ले।

चौधरी जय सिंह राठी: अब शक्लें देखने का आदि नहीं हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं अर्ज कर रहा था इनके नेताओं के बारमें, क्योंकि इन्होंने हमारे नेताओं के बारें में कुछ कहा बैक नैशनेलाईजेशन का इन्होंने शुरू से ढिढोरा पीटा कि ये किसी बैक को नैशनलाईज नहीं करेगे.....

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां बैक से क्या ताल्लुक है?

चौधरी जय सिंह राठी: हां जी बैंकों का ताल्लुक है क्योंकि उनसे पैसा मिलना था। (विघ्न)

उपाध्यक्ष: आप एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोले जो आपके आपने फायदा के लिए है! (विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठी: क्या यह कोई एप्रोप्रिएशन बिल फायदे का है? अगर फायदे का होता तो हमसे भी पूछते। (विघ्न)

उपाध्यक्ष: गवर्नमेंट कुछ भी करे हाउस से पूछ कर करती है। (विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठी: आप तो हमे यह पूछना चाहते है कि मार तो नही देगे। यह तो बाहर जनता में नही निकलते बिना पुलिस के। किसी भी गांवों में जाये पुलिस साथ होगी। इनके नेताओं का तो यह हाल है कि सुबह के वक्त कुछ कहना नही, रात को साढ़े दस बजे हुक्म हो गया प्रजीडेण्ट से आडिनैन्स जारी करा दिया कि राओं के प्रिवी पर्सिज खत्म कर दिये जाये। दिन को अभी बातचीत चल रही थी लेकिन रात को हुक्म हो गया। रात का आडिनैन्स जारी किये जाते है। फिर कहने लगे कि पालियामैंअ नही तोड़ी जायेगी।

श्री बनारसी दास गुप्ता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिब, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां सैण्ट्रल गवर्नमेंट की कार्यवाही पर डिसकशन की जा रही है या एप्रोप्रिएशन बिल पर?

उपाध्यक्षा: मेरा ख्याल है कि यहां एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोला जाये।

चौधरी जय सिंह राठी: मैडम, मैं इस पर ही बोलूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक चीज मुझ कहने में आपत्ति नहीं है कि जहां तक स्पीच का ताल्लुक है पिछले दो साल से इस हाउस में अपोजीशन की स्पीचिज ही मिलेगी, इन भाईयों की स्पीच का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये ने दूसरों को बोलने देते हैं न खुद बोलते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि सुबह की यह सूचना थी कि इस देश की पालियामेंट तोड़ी नहीं जायेगी लेकिन नौ बज राज को हुक्म हो गया कि पालियामेंट तोड़ दी गई हैं जितने भी नुकसान के काम यह सरकार करती है वह रात को करती है लेकिन इनका असर जनता पर इतना भयानक पड़ेगा जिस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आज किसी गरीब को बैंको से पैसा नहीं मिलता है लेकिन ये कहते हैं कि 4 करोड़ रुपया बचाने के लिए यह सब कुद यिा गया है।

उपाध्यक्ष: राठी साहिब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलिए and do not go beyond its scope.

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैडम, मेरी एक सबमिशन और है किसी मैम्बर की बोलने के लिए कोई टाईम लिमिट होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष: हाउस ही बताये कितना समय होना चाहिये?

श्री के०एल० पोसवाल: जो आप फिक्स करे दें, मैडम।

उपाध्यक्षा: आगे से किसी मैम्बर को 10 मिनट से ज्यादा नहीं दिये जायेगे मगर ये तो पहले सहे ही बोल रहे है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मैडम, क्या यह टाईम हम भी नोट करें? यह रिकार्ड के अन्दर है कि कल तो 15 मिनट दिये गये औ मुझ भी 15 मिनट दिये गये थे लेकिन अब आप दस मिनट कह रही है।

उपाध्यक्ष: अब तो हाउस का फैसला है इसलिए मैम्बर साहिबान एक मिनट भी ज्यादा नहीं बोल सकते। अगर हाउस 10 मिनट चाहता है तो 11 मिनट नहीं बोल सकेगा। राठी जी, आपको 5 मिनट और दिये जाते है।

चौधरी जय सिंह राठी: बात यह है कि जब इनके बोलने का वक्ता होता है तब तो कहा जाता है और टाईम और टाईम, और जब हमारा नम्बर आता है तो कहते है दस मिनट।

Deputy Speaker: Nobody will be allowed to take more than ten minutes.

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै अर्ज कर रहा था कि जो डिमांड्ज आई है हाउस में इन में राजाओं से प्रिवी पर्स देन के लिये भी रूपया मांगा गया है। जब इन्होने डिमांड भी पेश कर दी तो कैसे ये उसका हाउस में जिक्र करने से इनकार करते है? जो चीज हाउस में आ जाये उसको यह कैसे इनकार कर सकते है? उसका हम जिक्र कर सकते है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: बैकों का जिक्र नहीं कर सकते ।

चौधरी जय सिंह राठी: बैको से हमें कर्जा लेना है खुद आपने ही तो जिक्र किया था कि शराब बन्दी के लिए सैटर से साढे तीन करोड़ रूपया मिलेगा। इनके लिए पाबन्दी नहीं, हमारे लिय है, यह तो बड़ी अजीब बात है।

श्री के. एस. पोसवाल: वह तो रिटन आ चुका है।

चौधरी जय सिंह राठी: यह कही रिटन नहीं?

उपाध्यक्षा: आपके तीन मिनट और रह गये है। (हंसी)

चौधरी जय सिंह राठी: मैडम, मेरा तो मिनट कायम रहे वह भी बहुत है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मै बिजली के महकमें के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं बिजली के महकमे को कुछ पैसे दिये गये है कुछ ग्रान्टस दी गई है। इन्होने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर वगैरह बेचने के लिए एक कम्पनी हमारे पास आई। मै हैरान हो गया इनकी बात सनु ककि जो अफसर इनको सामन बेचने आया वह यही से नौकरी छोड़ कर गया था और इनके महकमें का बहुत पुराना नौकर था। पता नहीं ट्रक्टरों के मामलेमें बिजली के ट्रांसफर्मरों को कैसे ल आये। (विघ्न) मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या इन्होने किसी ऐसी कम्पनी से पूछाथा जो ट्रक्टर बनाती थी कि हमें बिजली के ट्रांसफार्मर चाहिये? उनके पास से इनको ट्रांसफर्मर कैसे मिल गये, यह बात मेरी समझ मे

नहीं आती? पता नहीं इन्होंने कैसे ट्रैक्टरों के ट्रासफार्मर निकला के रख दिये।

श्री के.एस. पोसवाल: वह अफसर तो खुद ऐसा सामान बेचने आया था।

उपाध्यक्ष: मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन्ट्रप्शन न हो।

चौधरी जय सिंह राठी: इन वजीरों को कहो, मैम्बर कोई कुछ नहीं कह रहा।

श्री के.एल. पोसवाल: मैं तो आपका प्वायंट कलैरिफाई कर रहा था।

Deputy Speaker: Mr. Rathi, you are talking to the Minister Please address the Chair.

चौधरी जय सिंह राठी: मैं अर्ज कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कोई नई बात नहीं की है पहले जो भाषझा गवर्नर साहब यहा पढ़ कर गये थे और बता कर गये है कि हम फलां फलां कामों में तरक्की कर देंगे तो वही कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। कोई चीज भी ये ऐसी नहीं करना चाहते जो कि जस्टिफाइड हो। फिर अपोजीशन पर ये इलजाम लगाते है कि वह हाउस को छोड़ कर भाग गई। हम तो यहां, बोलते है ओर हर रैलेवैट बात बताते है। लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और वह यह कि जब हम दो चार

क्रिटिसिज्म की बातें करते हैं तो ये बिगड़ जाते हैं और जब हम कोई सजौषन देते हैं ये हंस का टाल देते हैं कहते हैं कोई बात नहीं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबाबा, हम गिरे हुए नहीं हैं कि इनको गालिया देने लग जाये। गालिया देना बाहर की बात है। इन्होंने तो अदब सीखना नहीं लेकिन हमें तो अदब कायम रखना है।

उपाध्यक्ष: आपका टाईम हो गया है।

चौधरी जय सिंह राठी: मैडम, मैं कनकल्यूड कर रहा हूँ मैं अर्ज करूंगा कि यह जो ऐंप्राप्रिएशन बिल ले आये है इसमें अफसरों को छोड़ कर मुख्य मंत्री का या इनके वजीरों का थोड़ा सा भी हाथ नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा की तरक्की को ये बहुत पीछे ले जा रहे हैं अगर ये अफसर न होते। ये तो यहां जवाब देने के लिए भी तैयार होकर नहीं आते। इन्होंने यह कहा है कि गर किसी अफसर की नौकरी के दौरान बदकिस्मती से अचानक मौत हो जाये तो उनके परिचारों को ये कुछ सहूलियतें देगे मगर कितने ही अफसर इन्होंने दो दो साल से सस्पेंड कर रखे हैं अझैर वे तड़प रहे हैं (घंटी) डिप्टी स्पीर साहिब, मैं खत्म कर रहा हूँ यह कह कर कि इस सरकार की सब चीजे नंगी हो चुकी हैं, जनता इसके फेवर में नहीं है।, ये जो ऐंप्राप्रिएशन बिल लाये हैं मैं इसकी सख्त मुखलिफत करता हूँ और मैम्बर साहिबान से रिक्वैस्ट करता हूँ कि यह पास नहीं होना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबाबा, आज यह तो सप्लिमैन्टरी ऐस्टिमेंट्स पर एप्रोप्रिएशन बिल आया है, सुबह से मैं श्री बनारसी दास जी की इस हालत देख रहा हूँ। मुझे इनकी कुछ समय पहले की हालत या आ गई है। आज इनके अन्दर कुछ ताकत सी आ गई है। और मुझे खुद भी महसूस हुआ कि हमारी बिरादारी में भी इससे कुछ ताकत आ गई है पिछले दिनों जब कैबिनेट की एक्सपैशन हुई तो यहां से चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको टेलीफोन किया क्योंकि यह पार्टी के जनरल सैक्रेटरी है, कि मैं कैबिनेट की एक्सपैशन कर रहा हूँ आप फौरन पहुंचिए। इन्होंने उनसे नये आदमियों के नाम पूछे, तो उन्होंने नाम भी बता दिये। अब बिरादी तो इनकी, आपकी और हमारी एक ही है। लेकिन यह धोती बांधते हैं, जैसे अगर मैं बारह हूँ तो मैं भी धोती ही बांधता हूँ परन्तु ये जरा सरमायेदार हैं, इसलिए रेशमी कुर्ता पहनते हैं और टोपी भी लगाते हैं जब इन्होंने नाम पूछे तो चीफ मिनिस्टर साहिब हने लगे कि चौधरी नेकी राम, माडू सिंह, महावीर सिंह, और सूबेदार, यह सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं परन्तु जब नइका नाम आया तो आंखों से पानी निकलना शुरु हो गया और पानी से उनकी जूती भर गई। घर वालों ने यहा सोचा कि शायदा बाबू जी का पेशाब न निकल गया हो! आज इनकी ताकत देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मेरी बिरादारी के एक आदमी में कुछ हिम्मत तो आई है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह जूती जो थी, इन्होंने साफा की थी।

Deputy Speaker: Please speak on the Appropriation Bill.

श्री के० एल० पोसवाल: डिप्टी स्पीकर साहिब, थोडसे से हंसी मजाक को तो कई हर्ज नहीं.....।

उपाध्यक्षा: यह हाउस हंसी मजाक की जगह नहीं है।

श्री सत्य नाराण सिंगोल: मेरी अर्ज यह है कि पिछली दफा भी जब बजट सेशन था तो उसमें सप्लिमैटरी ऐस्टमेट्स जब आये तो मैंने हाउस में दो-तीन चीजों की मांग की थी और उनको पूरा करने के लिए फाईनैस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ने वायदा भी किया था। एक तो मैंने सफीदों में रैस्ट हाउस बनाने के बारे में कहा था जिस पर इन्होंने कहा था कि हम जरूर बनवा देंगे। वह न ऐस्टमेट्स में तो नहीं है। लेकिन नये बजट के अन्द जरूर है कि सफीदों में पी. डबल्यू.डी का एक रैस्ट हाउस बनवायेगे। इसके लिए मैं चौधरी रण सिंह का धनयवादी हूँ क्योंकि इन्होंने मेहरबानी करके उसे बनवा दिया है। एक चीज मैं जरूर कहूँगा.....।

श्री बनारसी दास गुप्ता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम, ये बजट का जिक्र कर रहे हैं। आपने पहले रोका था कि बजट का जिक्र न किया जाय.....।

Deputy Speaker: I will see, it is my duty.

श्री सत्य नारायण सिंगोल: वाह! महात्मा आनन्द! तो डिप्टी स्पीकर साहिबान मै इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि सफीदों के अन्दर किस भी आफिस के लिये ने तो अक्मोडेशन और न ही किसी अफसर के रहने के लिए जगह है। गवर्नमेंट ने एक सरकुलर निकाला था जिसके तहत जितने भी तहसील हैडक्वार्टर थे, तमाम के तमाम सब-डिवीजनल हैड-क्वाटर में चेंज कर दिये गए थे। एक सफीदों ही ऐसी तहसील है जो कि अभी तक भी तहसली हैडक्वार्टर ही है। जब भी इनकी कोई इम्पूवमेंट या डिवैल्पमेंट की स्कीम आती तो उसके अन्दर ये कहते हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जितने भी सब-डिवीजनल क्वाटर है, उन पर यह डिवैल्पमेंट करनी हैं हरियाणा के अन्दर सफीदों ही ऐसी तहसील है। जो सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर नहीं है। यह एक बहुत पुरानी तहसील है। इनसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि जहां यह डिवैल्पमेंट के कामों के लिए सब-डिवीजनल है वहां इस सफीदों तहसील को भी सब-डिवीजनल समरू कर इन्कल्यूड कर लिया करें क्योंकि इसका एक राइट था जोकि इसको नहीं मिला। इसलिए डिवैल्पमेंट की चीजों इसे साथ धक्के शाही नहीं होनी चाहिए।

इरीगेशन के लिए इन्होंने बड़ा पैसा मांगा है। इरीगेशन मिनिस्टर यहा बैठे हुए हैं पिछले दिनों जींद डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जींद डिस्ट्रिक्ट नं 3 जो कि बहुत लम्बी है, की तामता मोरियों का री-कन्सट्रक्शन किया गया है और वहां नये डिजाइन की मोरिया

लगाई गई है। मुझे तो पता नहीं कौन ठेकेदार था लेकिन किसी ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया गया जिसने कि काम ठीक नहीं किया और वे तमाम की तमाम मोरिया टूट गई है। मैंने इसके बारे में एक्स.ई.एन. और एस. ई. को चिट्ठी भी लिखी। मैं खुद भी वहाँ गया था और तीन चार मोरियों की हालत तो मैंने खुद देखी है सब मोरियों टूट गयी है और सरकार को चाहिए कि कम से कम जमींदार के ऊपर न लगाये और उसकी इन्क्वायरी करवये कि किस ठेकेदार ने वे गलत मोरिया लगाई है उसके बाद उन मोरियों को ठीक कराये और जब ये नये ढंग से मोरिया लगी है और जब तक वे रिपेयर नहीं हो जाती, जब तक का जमींदार के कोई नहीं तावाना लगाना चाहिए। इन्होंने तावाना को भी भी कमर तोड़ टैक्स बना दिया है। वह भी पहले से 20 गुना कर रखा है। जमींदार का इसके अन्दर कोई कसूर नहीं है। रामधारी जी पिछले दिनों वहाँ गये थे और एक जगह तो इन्होंने खुद देखकर ओरली का दिये थे कि वाइई राजवाहे की पटड़ी खराब है इसलिए जब तक इसको ठीक न कर दे यदि यहाँ कोई ब्रीच हो गया तो जमींदारों पर इसकी कोई जिम्मेदार नहीं होगी। उसके तीसरे-चौथे दिन वहाँ ब्रीच हुआ और उस ब्रीच को कट बना कर लोगों पर लगा दिया। इन्होंने खुद मोरखी, लुदाना या भवेवां, में से किसी एक गांव के अन्दर वायदा किया था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ तो तावाना लगाया गया है वह नहीं लगाना चाहिए।

इन्होंने दो तीन कालेजों का जिक्र किया है। एक बहादुरगढ़, एक राई और एक कालका। कालका तो खैर तहसील हैडक्वाटर है लेकिन न तो बहादुरगढ़ और न ही राई में तहसीले है और उनके मुकाबले में सफीदों बैकवर्ड और फलड अफैक्टिड एरिया है। हर तरीके से वह पशमान्दा हैं वहां के लोगों ने इनसे मांग की है कि वहां एक कालेज बना दिया जाए। एक लाख रूपया उन्हीं ने इकट्ठा भी किया हुआ है मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये कहे है कि हम बैकवर्ड और फलड अफैक्टिड एरिया है हर तरीके से वह पशमान्दा है। वहा के लोगो ने इनसे मांग की है कि वहां एक कालेज बना दिया जाए। एक लाख रूपया उन्हीं ने इकट्ठा भी भी किया हुआ है। मैं इनके रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये कहे है कि हम बैकवर्ड और फलड अफैक्टिड एरियाज की तरक्की करेंगे यदि औन मैरिट इन्होंने कुछ करना है तो सफीदों के लिए कालेज की बहुत जस्टिफिकेशन है और वहां पर कालेज का होना जरूरी भी है। मैं इनको एक नई चीज बताता हूं। अब तक इन्होंने तमाम के तमाम कालेज शहरों में खोले है। इसलिए शहरों की तरक्की हुई है। और देहातों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। एक राई का जो कालेज है यह पता नहीं किस तरह से से इन्होंने बनाया है मैं तो बहुत साफ आदमी हूं चौधरी मुख्तियार सिंह की बात इनसे रली-मिली है। पता नहीं इन्होंने वहां पर कैसे कालेज बनवा दिया है मेरी तरफ से इनको सजेशन है कि इनकों रुरल साइड मे भी कालेज खोलने शुरू करने चाहिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तालवा बहुत बड़ा गांव है

वहा यदि आप कालेज खोल दे तो हम आपको जितनी जमीनकी जरूरत होगी दे देगे बिल्डिंग भी जा हम हाई स्कूल के लिए 10-15 कमरे बना रह है वही दे देगे। मेरी यह सजेशन भी है कि आप वहा पर एक कालेज खोल दे। वैसे मेरा अपना गांव नी है, लेकिन मेरे ऊपर उनके अहसान जरूर है। जुई नहर की यह बड़ी डीगे मारत है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने यह नहर बनाई, यह भी ठीक, तीन महीने पानी देगी, यह भी ठी, लेकिन ये जो कहते है कि देसरे जिलों का पानी कट नही किया, यह गलत है। इन्होंने एक हिसाब लगा रखा है जो कि मैं समझ रहा हूं और वे ऐसे है कि जो शुरू से पानी चला आ रहा है वह तो उसकी रेशों बांटते है और शायद उस रेशो से हामर जिले का भी पानी देते है होंगे लेकिन जो फालतू पानी व्यास लिक का आना है उसमें कहे है कि आपका हाथ नही है। यदि किसी जमीदार को पानी की जरूरत हो और यह फालतू पानी हमारी ही नहरों में से हमारे सामने से होकरी गुजरे, और ये उसको वह पानी न दे, तो उसको बहुत महसूस होता है। ये जो कहते है कि वहां 3 महीने पानी न दें, तो उसको बहुत महसूस होता है। ये जो कहते हे कि वहां 3 महीने पानी देंगे, यह तो एक ढोंग है वरना इस बात को तो ये भी ऐडमिट करते होंगे कि नौ महीने उस इलाके में आक पैदा होगा। अगर वहां पानी तीन महीने नही जाना है तो फिर इसके अन्दर जो नहर जमनगर्बी के साथ साथ ये 500 या 600 ट्यूबवैल लगा रहे है यह उस तमाम पानी को उन नहरों में इस्तेमाल करना चाहते है। सब मोरियों के अन्दर उस पानी का इक्वल डिस्ट्रिब्यशन हो और

उसी रेषों के हिसाब से यह पानी सब को मिलना चाहिए और अकेल हुई नहर के अन्दर नहीं जाना चाहिए। इन्होंने 2 हैलीकॉप्टरों की डिमांड की है और कहते हैं हम हैलीकॉप्टर खरीदेंगे।

उपाध्यक्षा: आपका टाईम हो गया है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मैडम, दो मिनट तो बाकी होंगे।

उपाध्यक्षा: अच्छा! आप दो मिनट और बोल ले.....
....।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: डिप्टी स्पीकर साहिब, हैलीकॉप्टर की जरूरत या तो कपास की फसल या फिर ईख की फसल पर स्प्रे करने के लिए पड़ती है। गेहू या चने पर तो इससे स्प्रे नहीं हो सकता क्योंकि इससे फसल नष्ट हो जायेगी। अब न तो कपास की फसल आनी है और न ही ईख की सीजन है। अब तो इनकी अप्रैल मई में काश्त की जायेगी। बरसात क मौसम में जाकर कहीं उनको स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। इस साल में यह सरकार 10 लाख रूपये जो खर्च कर रही हैं यह बिल्कुल नाजायज मांग है। और उस पर अब यह खर्च नहीं करना चाहिए। इस खर्च को नैक्सट ईयर के लिए पोस्टपान किया जा सकता है। और इस पैसे को किसी और अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहा चौधरी खुरशीद अहमद साहत बड़े तम तड़ाक से बोलते हैं।

पिछली दफाा इन्होने मेरे से वायदा किया था कि कुछ पैसे इनके डिपार्टमेंट बच गये थे। मेरे से कहने लगे कि मैने काफी पैसा बचा करके सफीदों के अस्पताल के लिये दे दिया हैं मैने बहुत कोशिश की पता लगाने की परन्तु न तो उस बारें मे हैल्थ डिपार्टमेंट कुछ बता रहा है और न ही पी०डब्ल्यू०डी० कुछ बता रहा है कि वह पैसा है कहां? सफीदों के अस्पताल को अपग्रेड हुए कम से कम एक साल हो चुका है लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग के ऊपर एक पैसा भी खर्च नही आया। वहां दो तीन क्वार्टर इन्हाने जरूर स्टाफ के लिये बनाये है लजेकिन जाहं तक हास्पिटल की अकमोडेशन का ताल्लुक है वह यों की यों है। जब तक वहां अकमोडेशन नही बतनी तब तक वहां न तो बिस्तरों का इन्तजाम हो सकता है और नही किसी दूसरी चीज का। मै इन से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो पैसा पिछला था और इन्होने उस अस्पताल के लिए दिया था, कम से कम उस पैसे को तो वहा लगा दे ताकि उस पैसे से अस्पताल की कुछ अकमोडेशन बनाई जा सके और इस फ्लड-अफैक्टिड एरिया के अन्दर अच्छा काम हो सके। मै आपका धन्यवाद करता हूं और ख्याल करता हूं कि गवर्नमेंट मेरी बात पर ध्यान देगी।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, सप्लिमैन्टरी ऐप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा हम चार करोड़ से ऊपर की मां मंजूर कर रहे हैं आजकल प्लानिंग का युग है आम तौर पर अच्छा तरीका बजटिंग का यह है कि जिन चीजों का हम को पता

है ये हमने करनी है उनका जिक्र तो बजट में होना चाहिए और कुछ चीजें जो बाद में आएँ उनके लिए सप्लिमैन्टरी एस्टिमेट्स लाए जाये लेकिन यहां तो हालत ही दूसर हैं बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हर जगह सड़क बना देगे, पानी का इन्तजाम करे देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आज से पांच वर्ष पहले जिन सड़कों की मंजूरी दी गई थी, वे सड़क आज तक की नहीं बनी हैं तो अब जिन सड़कों की मंजूरी दी जा रही है वे 1972-73 तक कैसे बन सकेंगी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): बनाने से बनेंगी।

चौधरी रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि श्री खुरशीद अहमद के जिले वाले सहयोगी के पास बिजली का महकमा गया था तो ये कहने लगे कि रोहतक को बिजली नहीं मिलेगी।

श्री खुरशीद अहमद: यह तो आपने कहा होगा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा।

चौधरी जय सिंह राठी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। क्या जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो मिनिस्टर साहिब इंटरफीयर कर सकते हैं?

उपाध्यक्षा: मैं खुद यह चाहती हूँ कि इंटरफीयर न हो जिससे हाउसा का काम ठीक तरह से चल सके। It is up to me. If any Honourable Member speaks no body should interfere.

लोक निर्माण मंत्री (श्री रण सिंह): मैं चौधरी साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि जो सड़कें पांच साल पहले मंजूर हुई थीं और अब तक नहीं बनी हैं उनके नाम बता दें ताकि उनको बना दें।

चौधरी रणबीर सिंह: जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि मैं उन सड़कों के नाम बताऊँ तो सारी सड़कों के नाम तो इस समय मुझे याद नहीं हैं क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी सड़कें थीं जो उस समय मंजूर की गई थीं और एक सड़क तो चौधरी रणसिंह के हल्के में भी मंजूर की थी।

श्री रणसिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। अगर ये सही बातें तो अच्छा रहेगा जिस सड़क का का ये जिक्र कर रहे हैं वह तो मैंने ही मंत्री बनने पर मंजूर की है। इन्होंने नहीं।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, यह तो प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह: मेरा तो ख्याल था कि लोक निर्माण मंत्री शायद हौसले से सुनना चाहेंगे। मुझे को इसमें कोई एतराज नहीं है कि वह सड़क इन्होंने मंजूर की हो लेकिन यह सरकारी कागज तो मैं नहीं बनस सकता। अगर मंत्री महोदय इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं आज ही शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भेज देता हूँ कि 1966 में कौन कौन सी सड़कें मंजूर की गई थीं और कौन कौनी सी बनाई गईं?

श्री रण सिंह: आप नोटिस दीजिए। मुझे आपत्ति नहीं।

चौधरी रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, मुझे मालूम है कि सरकार ने एक योजना बनाई थी जो 25 प्रतिशत, चाहे जमीन की शकल में, मजदूरी की शकल में, मिट्टी की शकल में या नकद पैसा देगा वह सड़क हम गांव तक बना देगे। मुझे पता नहीं वह योजना अभी चल रही है या नहीं।

श्री रणसिंह: वह खत्म कर दी है।

चौधरी रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, यह खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक अवस्था अच्छी हुई है। हमारी साख अच्छी हो गई है, हमें कर्जा मिल जात है है यह भी खुशी की बात है कि हम बारह करोड़ रूपए सड़कों पर खर्च करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्षा: आपके तीन मिनट और रह गए हैं।

चौधरी रणबीर सिंह: यह तो ठीक है लेकिन ये लोग मुझे दुसरी तरफ ले जाते हैं वह टाइम कहा जाएगा? उसका हिसाब कौन रखेगा।

उपाध्यक्षा: उसका हिसाब मेरे पास रहेगा।

चौधरी रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, जो सड़के हैं उनमें से कुछ का नाम मैं बता सकता हूं। मेरे गांव की सड़क पांच साल हो गए हैं। आज तक नहीं बनी, मेरे पड़ोस में पड़ने वाली

सड़कों के नाम ही मैं बता सकता हूँ। मेरे गांव का नाम सांधी है। उस गांव की सड़क अभी तक नहीं बनी। धामड़ और चमारियों की सड़कें भी आज तक नहीं बनी।

उपाध्यक्ष महोदया, मुझे को मालूम नहीं कि ये मेरे हल्के को कौन सा मानते हैं? मुझे को तो गिला इस बात का है कि मैं कांग्रेस पार्टी का मैम्बर हूँ (विधन) चौधरी जय सिंह राठी भी कांग्रेस के मैम्बर थे जब लोगों ने उनको चुना था।

चौधरी जय सिंह राठी: मैं तो चौधरी साहब, अब भी कांग्रेस का ही मैम्बर हूँ, असली कांग्रेस का।

चौधरी रणबरी सिंह: खैर, मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि किलोई हल्के में जिसको मैं रिप्रिजेंट करता हूँ, चाहे कोई पानी की स्कीम है, चाहे सड़कों की स्कीम है और जिन स्कीमों के लिए पैसा भी लोगों ने दे रखा है, फिर भी उनको नजरअन्दाज किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह कोई पाकिस्तान का इलाका है या यू.पी. का हिस्सा है या पंजाब का इलाका है। किलोई के हल्के को आप हरियाणा में मानते हैं कि नहीं (विधन)

उपाध्यक्ष: इन्ट्रप्ट न करें।

चौधरी रणबीर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे खुशी है कि हम हरिजन कल्याण निगम बनाने जा रहे हैं लेकिन मैं यह

कहे बिना नही रह सकता कि उसक लिए हमने जितना पैसा कहा था उतना पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आपक को तीन मिनट ज्यादा दिए जाते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह: मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उपाध्यक्षा महोदया, इसी तरह से एक सवाल पूछा गया था कि कितने बैकवर्ड कालसजि के लोगों को नौकरियों दी गई है। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर यह भी सवाल पूछा गया था कि कितने आफिशियलज मुअत्तल हुए हैं लेकिन उसका को भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूरी जिम्मेवादी के साथ कह सकता हूँ कि आज भी सरकार के पास बाकायदा क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, हो सकता है कि वह पहली जनवरी, 1971 तक न आई हो लेकिन उससे पहले क्वार्टर की रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद थी। इनके पास यह रिपोर्ट थी कि कुल कितने मुलाजम मुअत्तल हुए हैं, छः महीने से ज्यादा कितने हैं और साल से ज्यादा कितने हैं, अगर गवर्नमेंट यह बताने के लिए तैयार नहीं तो फिर उनका भला क्या हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने सरकारी मुलाजमों की बात बताई कि हम उनको इनामात देते हैं मैं यहां पर अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर एक बड़ी अफसोसनाक घटना हुई थी। एक सरकारी मोटर किसी कार के साथ टकरा गई जिस में तकरीबन छः सात आदमी मारे गए। उस में एक तो चौधरी माडू सिंह जी, जो हमारे मंत्री हैं,

उनकी लड़की थी, मेरी भतीजी भी उसमें से थी और इकके अलावा कुछ और नन्हे बच्चे थे वे जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। उस ऐक्सीडेंट में चौधरी जसवंत सिंह, जो उस वक्त उप मंत्री थे उनका ड्राइवर और गनमैन भी मारा गया था उस का दावा हुआ और उस दावे के अन्दर बीस-बीस हजार की डिग्री हुई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि और मदद तो दूर रही सरकार ने अभी तक उसे डिग्रीकी पेमेंट भी नहीं की। अगर राजनीति के बेसिज पर व डिग्री रोकी जा रही है क्योंकि चौधरी जसवंत सिंह, जा चौधरी सूरज मल क लड़क है है वे उस वक्त विरोधी कदल के उप मंत्री थे, तो यह बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। अगर इस ख्याल से उन की डिग्री रोकी भी गई थी तो दूसरों को तो पैमेंट कर देनी चाहिए थीं उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी माडू सिंह और मैं कांग्रेसी हैं जैसा मैं पहले बता चुका हूँ उसमें एक चौधरी साहब की लड़की थी और दूसरी मेरी भतीजी थी। अगर हमारे चौधरी सूरज मे के साथ रिश्तेदार होगई ते इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि उनके हम में जो डिग्री हुई है वह उनको दी न जाए? मैं समझता हूँ कि यह सरकार के लिए जायज बात नहीं है। सरकार को ऐसे कामों में लोगों को हाई कोर्ट में जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह कोई शोभा वाली बात नहीं है। इसी तरह जो दीगर सरकारी मुलाजमों के हक में डिग्रियों हुई है वह भी सरकार को जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। हर बात क लिए लोगों को हाई कोर्ट में जाने के लिए मजबूर नहीं करन चाहिए क्योंकि उससे हमारे प्रदेश की शोभा नहीं बढ़ती और इसके

इलावा खजाने पर और भी बोझ पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। बाकी जो तकलीफों में इमदाद करने की नीति गवर्नमेंट ने रखी है मैं उस का स्वागत करता हूँ। आप का धन्यवाद।

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खां): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिन मामलात पर आज बहस हो रही है मुझे अफसोस यह है कि उनका एक बहाना बना कर (विघ्न)

श्री सत्य नारायण सिंगोल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, खान साहब के महकमें के बारे में तो कोई बात नहीं कही गई?

Deputy Speaker: But if he wants to speak he can. Any Minister can participate in the discussion in the House.

श्री अब्दुल गफ्फार खां: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं करनी चाहता बल्कि मैं उन बातों के लिए अफसोस का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिन का कि हमारी स्टेट से या ऐप्रोप्रिएशन बिल से कोई ताल्लुक नहीं था बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि यहां किसी पर इलजाम लगा दिया जाये क्योंकि किसी की जबान को रोकने वाला तो कार्ड है नहीं। अगर यह बात है और खासतौर पर हाउस क अन्दर तो जो दिल में आए कह जाओं। मुझे अफसोसा है कि यहां परबगैर जिम्मेवारी क उन लागों पर कटाक्ष किया गया है जो आज हिन्दुस्तान के महबूब लीडर समणे जाते है। और जो हिन्दुस्तान को

तरक्की की रहा पर ले जाना चाहिते है। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। मेरा इस वक्त दिल भरा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन लोगों ने जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिन्दगी गुजार दी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उनके बामरें मे इशारतन या वैसे यह कहा जाये कि वह करते कुछ है और कहते कुछ है तो यह गैरमुनासबि बात है तीन पुश्तसे उस खानदान का कमा सिपाहगिरी चला आ रहा है वह उस दादा की पोती है जिनका नाम पंडित मोती लाल नेहरू है और व उस बहादुर की बेटी है जिसन हिन्दुस्तान का नाम तमात दुनिया में मशहूर किया है और जिसका नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू है.....
.....।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस मे जो बहस चल रही है वह ऐप्रोप्रिएशन बिल पर चल रही है और उसमे इस बारे में कोई जिक्र नहीं जिसका खान साहिब यहां चर्चा कर रहे है और तकरीर फरमा रहे है। इसमें यह सब कुछ कहा से आ गया?

उपाध्यक्षा: खान साहिब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोले।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: मै तो जनाब ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोल रह हूं और इन साहिबान ने जो कुद इस बिल पर बोलते हुए कहां है उसका जवाब दे रहा हू।

उपाध्यक्षा: मेने उस वक्त इन को भी चैक किया था जब वह आउट आफ वे जा रहे थे।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: जो बातें इन्होंने कही हैं मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका जवाब दूँ।

उपाध्यक्षा: ठीक है, आप अपना फर्ज अदा करें लेकिन ऐप्रोप्रिएशन बिल पही ही बोले.....।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: जिसके बारे में इतनी बातें हाउस में कही गई हैं।

उपाध्यक्षा: ठीक है और मैंने उनको चैक किया था वहा हाउस है, पब्लिक प्लेटफार्म नहीं है।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: चलो मैं यह बात छोड़ता हूँ लेकिन मैं पूछता हूँ कि [* * * *] यह हिन्दूस्तान की बहादुर बेटी कश्मीर की लड़ाई में हाजीपीर की चोटी पर खड़ी हो गई थी। सामाने निशाना है, जनरल कह रहा है कि एक तरफ हट जाओ वरना सीधा निशाना तुम हो लेकिन वह बहादुर बेटी हिन्दुस्तान की जिने हिन्दुस्तान को मशहूर किया उस से मस नहीं हुई। उस वक्त वह प्राईम मिनिस्टर नहीं थी.....।

चौधरी जय सिंह राठी: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। काश्मीर की लड़ाई किसी की बाहदुरी, किसी का हाजीपरी

की चोटी पर खड़ा होना और किसी जनरल को कुछ कहना, क्या ये सब कुछ ऐप्रोप्रिएशन बिल का हिस्सा है?

उपाध्यक्षा: यह तो मैं मानती हूँ कि वे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर नहीं बोल रहे हैं लेकिन वे मिनिस्टर हैं इसलिए उनको हक है कि जो बातें यहां पर उठाई गई हैं उनका जवाब दें। क्योंकि राठी साहब ने इस बात का उठाया था इसलिए उसका वे जवाब दे रहे हैं और उसका उनको हक है।

चौधरी जस सिंह राठी: अगर वे मेरी स्पीच पढ़ कर साबत कर दें कि मैंने कुछ कहां हो तो मैं मान जाऊंगा। हिन्दूस्तान की बेटी न कोई उस वक्त प्राईम मिनिस्टर थे और प्राईम मिनिस्टर के बारे में कोई बात मैंने कही ही नहीं और उस वक्त वह लड़ाई हुई वहा प्राईम मिनिस्टर नहीं थी और उस वक्त के प्राईममिनिस्टर का मेन कोई जिक्र नहीं किया।

उपाध्यक्षा: अगर आप अपनी स्पीच में बैंकस वगैरा को ला सकते हैं तो उन्होंने तो बतौर मिनिस्टर उसका जवाब देना है।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: तो जनाब मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ यहा इनसिनुसेशन किये गये और क्या हम नहीं समझते कि जो ये बातें इशारतन और किनारतनकरते हैं और ये करते रहे। तो मैं कह रहा था कि जनरल का कहना था कि एक तरह हट जाओ क्योंकि आप सीधा निशाना हो लेकिन उस बहादुर बेटी ने कहा कि जब लोग खड़े हुए हैं और अपनी जान देने के लिए

तैयार है तो मुझ जान की परवाह नहीं। वे उस वक्त प्राईम मिनिस्टर नहीं थी। उनके दिल में यह दर्द था.....

उपाध्यक्षा: देखिए खान साहब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोले और उन की बातों का जवाब दे और जो बातें उन्होंने नहीं कही उनके बारमें में न बोले

Sh. Abdul Ghaffar Khan: May I request the Deputy Speaker to kindly tell me whether what they said was on the Appropriation Bill or was it beyond its scope.

उपाध्यक्षा: यह ठीक है कि वह आउट आफ दि वे गये है। (शोर)

श्री अब्दुल गफ्फार खां:

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

चौधरी जय सिंह राठी: आन ए प्वायंअ आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन, मैडम। खान साहब ने एक बात कही कि जिस वक्त वह हिन्दुस्तान की बेटी हाजीपीर की चोटी पर खड़ी थी तो आपके * * * * कहां थे और यह मुझ पर उन्होंने डायरेक्ट चोट की है।

आवाजे: उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। (शोर)

श्री अब्दुल गफ्फार खां: मैंने ऐसा नहीं कहा और किसी पर चोट नहीं की

चौधरी जय सिंह राठी: आपने कहा है और मेरे * * * *
के बारे में कहा है आप रिकार्ड देख लें.....(शोर).....
.... ।

उपाध्यक्षा: आर्डर प्लीज । मैं रिकार्ड से देख लेती हूँ कि क्या कहाँ गया है ।

श्री अब्दुल गफ्फार खा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने जितने भी तरक्की के काम किये हैं वे अफसरान की मेहरबानी से किए हैं । हमारी खुशकिस्मती है कि हमें निहायत ही काबिल और लायक अफसरान मिले हैं । ये अफसर पहली मिनिस्टरी में भी रहे होंगे, उस वक्त क्यों नहीं ऐसे कमा किये जो हमारी मिनिस्टरी ने करके दिखाये हैं । यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अफसर निहायत काबिल हैं यह कहना कि साहब आपने कौन सा घर से पैसा लगा दिया है, आपने कौनसा तीर मान दिया है, सड़के बना दी है या नहरें बना दी है, यह कर दिया, वह कर दिया—ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है । जनाब, गवर्नमेंट जो पालिसी बनाती है उस पालिसी को इम्पलीमेंट करने के लिए अपने अफसरान से दरखास्त करती है ।

उपाध्यक्षा: देखिए मैंने रिकार्ड देख लिया है और खान साहब, आपने यहाँ कहा कि * * * * जब यह हिन्दुस्तान की बहादुर बेटी कश्मीर की लड़ाई में हाजीपीर की चोटी पर खड़ी हो गई थी..... ।

चौधरी जय सिंह राठी: इसलिए तो मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। यह साफ तौर पर मेरे * * * * के बारे में कहा गया है.....(शोर) अब उसका जवाब भी सुन लो.....(शोर).....

श्री अब्दुल गफ्फार खां: मैं अब भी कहता हूँ कि कहां थे वे लोग जिस वक्त वहा बहादुर बेटी वहा खड़ी थी.....
(शोर).....

उपाध्यक्षा: उन्होंने खुद ही ठीक कर दिया है और कहा है कि कहां थे वे लोग.....तो यह आम बात है और किसी एक के बारे में नहीं है, जनरल बात है। यह आपके बारे में राठी साहब नहीं कहा गया.....(शोर).....वे कहते हैं कि उनकी सैस यह थी। तो मैं यह करैक्ट करवा देती हूँ कि * * * * की जगह 'कहां थे' वे लोग' कर दिया जाए.....

चौधरी जय सिंह राठी: मैं भी तो उन लोगों में शामिल हूँ जिन के बारे में उन्होंने कहा है। तो मैं खान साहब को बताना चाहता हूँ कि * * * * (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, खान साहब ने ये लफ्ज भूल से कह दिये थे लेकिन राठी साहब को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। यह बहुत बुरी चीज है।

Ch. Jai Singh Rathi: I withdraw these words.

उपाध्यक्षा: इन्होंने मान लिया है और जो लफज अच्छे नहीं है उनको विदद्दा कर लिया है।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि खान साहब के मुंह से कुछ शब्द इनएडवर्टेंटली निकल गये थे जिन का डायरैक्ट हिट इन के बुजुर्गों पर नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि राठी साहब ने आपने ऐक्सप्लेनेशन में खान साहब पर पर्सनल अटैक किया है (व्यवधान) This is a very sensitive thing. Such things should not be mentioned. It was in good taste.

उपाध्यक्षा: इन्होंने अपने लफज विदद्दा कर लिए हैं, इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे और मेरे खानदानकी कोई बात नहीं.....

उपाध्यक्षा: खानदान के बारे में जो लफज 'बजुर्ग वगैरह' इस्तेमाल किये गये हैं, वे ऐक्सपंज किए जाये।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: मैं अर्ज कर रहा था कि यह कहना कि पैसा तुम कहां से लाए हो, जो खर्च कर दिया, गलत बात है। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मैम्बर या कोई भी आदमी अपने पास से पैसा नहीं लगा सकता क्योंकि तमाम मुल्के के लिए या तमाम सूबे के लिए इतनी ताकत किसी में नहीं होती जो अपने पास से सारा पैसा लगा दे। सूबे की तरक्की के लिए आम जनता

टैक्सों के जरिए से पैसा देती है। टैक्स के जरिए से पैसा वसूल होता है और उस पैसे के जरिए से जो लायक गवर्नमेंट होती है वहा पालिसी बनाती है और उस पालिसी के लिए अपने अफसरान से रिक्वेस्ट करती है कि वे उस पर अमल करे।

चौधरी जय सिंह राठी: यह क्यों नहीं कहते कि जनता का पैसा वजीर न खाये?

श्री अब्दुल गफ्फार खां: हमने कब कहा कि हम अपना अपना पैसा लगाते है। क्या किसी मिनिस्टर ने कहा, क्या फाईनैन्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने अपना पैसा लगा दिया? हाउस इस बात को जानता है कि हमारी गवर्नमेंट ने कितनी शानदार पालिसीज बनाई.....

उपाध्यक्षा: खान साहब, आपको बोलते हुए पंद्रह मिनट से ज्यादा टाईम हो गया है, अब खत्म करें।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: नहीं जी, आप टाईम निकाल लें, हिसाबा कर लें कितना टाईम हो गया है।

उपाध्यक्षा: 22 मिनट हो गये है।

श्री अब्दुल गफ्फार खां: सिर्फ एक मिनट और दे दें। डिप्टी स्पीकर साहिब, यहां पानी की बाबत और दूसरी बातों की बाबत बातें हुईं। मुझ अफसोस है कि मेरे निहायत करीबी दोस्त, मेरे दिली दोस्त और कलगी दोस्त, जिन से मैं अलग नहीं हो

सकता और न ही वे मठ से अलग हो सकते हैं, चौधरी रणबीर सिंह जी इस वक्त हाउस में मौजूद नहीं हैं। जब ये वजीर थे तब आपको मालूम है कि अम्बाला जिला में कितनी सड़कें थीं? जा-जा कर इनके पास और चौधरी रिजक राम के पास दरखावास्त करते थे कि यहां सड़क बना दी जाये लेकिन बावजूद बार बार दरखावास्त करने पर इन्होंने सड़क नहीं बनवाई। चौधरी रणबीर सिंह जी ने बहुत पहले अम्बाला छावनी से बबियाल तक एक सड़क बना दी थी। आप जा कर देख लें उनके अपने गांव तक पक्की सड़क जाती है। चौधरी रिजक राम के गांव में जो मुश्किल से चार फर्लांग का फासला है, पक्की सड़क जाती है इन्होंने अम्बाला जिला में सिर्फ एक बबियाल तक बनई थी लेकिन हमें कहते हैं फलां जगह सड़क नहीं गई, फलां जगह यहा नहीं हुआ, वह नहीं हुआ जब ये खुद मिनिस्टरी में थे तो इन्होंने क्या काम किया, कितनी सड़कें बनाईं? आज हमें कहा जाय कि सड़कें नहीं बनईं यह कहा तक सही है, कोई छूमन्तर तो नहीं जे सारीसटेट में एक दम बना दें। तमाम सूबे की जरूरतों को सामने रखकर सलौली एंड स्टैडीली हम सारे कम करेंगे। हमारा गोल यह है कि किसी इलाके को नहीं बल्कि तमाम सूबे की तरक्की देकर जमीं से आसमां तक पहुंचा दें। इन काम में खुदाबन्द अल्ला ताला हमारी मदद करेगा, जनता हमारे साथ सहयोग करेगी। हमें यकीन है कि हम अपने सूबे को, जो कि सूबा नहीं बल्कि एक सूबी की तरक्की के लिहाज से तमाम हिन्दुस्तान से सूबों से आगे रखेंगे। पिछली अढ़ाई अर्से में इस छोटे से सूबे की हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि

अमरीका के अखबारों में चर्चा हुई कि इतने छोटै से सूबे ने सारे प्रदेश में बिजली लगा दी। मै यह नही कहता की हाथ लगा कर देख लो, झीक है किसी जगह नही पहुंची होगी, करंट नही गया होगा लेकिन इतना जरूरी है कि बिजली के साधन पैदा कर दिए है, सारे सूबे में बिजली लगाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है और जो कदम बढ़ाया है वह तमाम दुनिया में बेनजीर है, का मुकाबला कोई दूसरा सूबा नही कर सकता, चाहे कितना ही बुरा भला कहें। दुनिया हमारी तारीफ करती है लेकिन जो तारीफ न करें उस का इलाज क्या हो सकता है?

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै एक बात कहना चाहता हूं। अच्छे दोस्त का यह कायदा है कि वह पगड़ी की तरफ, टोपी की तरफ देखता है कि आया वह साफ है, उमदा है या नही। जो मुखालिफत है वह हमेंषा जूते की तरफ देखता है कि इसका जूता टूटा है या नही। मै एक और बात कहकर खत्म करता हूं। आप एक जगह फल या इतर रख दें और दूसरी तरफ गंदगी का ढेर लगा दे। कम्बखत मक्खी फूलों की तरफ नही जाएगी, गन्दगी की तरफ जायेगी। यही हाल इनका है।(हंसी)

श्री भगवान दास सहगल (अम्बाला कैंट): डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे हल्का अम्बाला कैंट में दो मैजिस्ट्रेट है मगर अफसोस की बात है कि वहां गवर्नमेंट की तरफ से कोई कचहरी की बिल्डिंग नही बनी हुई। आजकल कचहरी एक प्राईवेट कोठी में है। वहां कोई स्टैम्प फरोश भी नही है। जिससे कि लोग कागज और

स्टैम्प वगैरा ले सकें। एक दस पैसे का कागज लेने के लिए भी अम्बाला शहर जाना पड़ता है। जो कि वहां से पांच मी है। इससे वैसे दिककत तो सभी की होती है परन्तु बूढ़े और बुढ़ियों को ज्यादा तकलीफ होती है। इस कचहरी की बिल्डिंग में आर०टी०, अम्बाला के सैक्रेटरी भी बैठते हैं मगर अफसोस की बात है कि वहां पीने के पानी तक का इन्तजाम भी नहीं है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि बाकी जिलों में जहां इतना पैसा खर्च किया जा रहा है वहां मेरे जिले की ओर भी ध्यान दिया जाय और कचहरी की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बन कर तथा दूसरी सुविधाएं जिनका मैंने जिक्र किया है देकर वहां के लोगों के ऊपर भी कृपा की जाए।

वित्त मंत्री (श्रीमती प्रभा जैन): माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर जो कई बातें कही गईं उनका डायरेक्ट सम्बन्ध इन डिमांडों से नहीं था। बहुत सी बातों का जवाब खान साहब ने दे दिया है और मुझे कोई लम्बी चौड़ी बात कहने की नहीं रहती। राठी साहब एक पोलिटिकल बात को ख्वामखाह यहां कह गए ओर प्राईम किनिस्टर वाली बात को चाहे इन्होंने इशारतन कही जिक्र किया मगर बेहतर होता अगर वे उस बात को यहां न करते क्योंकि प्राईम मिनिस्टर, इंडिविज्यूयल कैपेसिटी में नहीं बल्कि स्टेटस के लिहाज से सारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी नेता है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगी। कि उनके सहयोग से पीछे भी यहां बहुत या काम हुआ है

और इस साल के बजट में भी कई स्कीमें उनके सहयोग के कारण ही शामिल की गई है। ड्राई फारमिंग के लिए जो नई स्कीम सितम्बर, 1970 में गवर्नमेंट आफ इंडिया से भेजी गई थी और जिसका खास तौर पर बैकवर्ड तथा रेगीस्तानी इलाकों को फायदा होगा, उसका भी जिक्र है। मैं समझती हूँ कि आज नई आर्थिक व्यवस्था के लिए जो प्रेरणा हमें उनेस मिल है वह हम सब लोगों के लिए फख्रा की चीज है।

राठी साहिब ने सड़कों के बारे में कहा कि बहुत पहले ही गवर्नर रूल में उनका फैसला हो गया था और अब तो यह सरकार केवल उन फैसले को एक्सीक्यूट कर रही है। मैं उनेस कहना चाहती हूँ कि गवर्नर रूल से पहले जो प्लान बनी थी वह सिर्फ 169 करोड़ की बनी थी उसमें सड़कों के लिए केवल 10 करोड़ रुपये खर्चा रखा था उसका बाद एनुवल प्लान बनती रही। फोर्थ फाईव ईयर प्लान जो दो साल पहले शुरू हुई थीं और उसमें जितना पैसा रखा था पांच साल के लिए उससे ज्यादा पैसा हम दो साल में खर्च कर चुके हैं। अगले साल के लिए हमने 12 करोड़ का प्रोविजन रखा है और इस साल में रोड प्लैन पर ही तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया खर्च किया है। कहां दो साल में हम अकेले 19-20 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और कहां पांच साल में दस करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अगर ये इस हवाई ख्याल में हो कि यह गवर्नमेंट पुरानी स्कीमों को एक्सीक्यूट कर रही है तो वह गलत ख्याल है। और सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बात है।

श्री के.एल. पोसवाल: यह तो ताजमहल के बनाने वाले है ।

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे एक सबमिशन करनी है ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें ऐक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं ।

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़ी छोटी सी सबमिशन है । मैं गुड ह्यूमर और गुड टेस्ट में बात कर रहा हूँ । मुझकों जा बात कहनी थी उसमें एक बात याद आ गई । किसी ने कहा है कि:—

मारे जाते है फरिश्तों के लिखे पर नाहक

आदमी कोई हमारा दमें तहरीक भी था ।

उसमें हमारा कोई आदमी नहीं था । ये ततो ऐसे ही बात कर है ।

श्रीमती ओमप्रभा जैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, शेर तो इन्होने बोल मगर इसमे कोई आनन्द नहीं आया ।

उपाध्यक्षा: आनन्द वाले शेर तो आपकी तरफ से होंगे ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: बोलते तो ये भी अच्छा है, मगर यह शेर अच्छा नहीं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंगोल साहन ने

सफ़ीदों के रैस्ट हाउस की बात कही। बाद में में इन्होंने तसलीम भी किया कि सप्लिमेंटरी ऐस्टिमेंटस में उसका जिक्र नहीं आया मगर अगले साल के बजट में हय इंकलूडिड है।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: मैने तो धन्यवाद किया था।

श्रीमती ओमप्रभा जैन: फिर तो आपका भी धन्यवाद। सफ़ीदों कालेज के बारे में भी इन्होंने कहा। मुख्य मंत्री जी वहा गए थे और लोगों से उन्होन कहा था कि अगर कुछ हिम्मत लोग करेगे तो सरकार अवश्य ग्रांट देगी। राई और बहादुरगढ़ में जो कालेज बने है उनके बारमें में अर्ज यह है कि राई में जमीन की कोई प्रौब्लम नहीं थी इसलिए कालेज बन गया ओर बहादुरगढ़ में लोगों ने जमीन देने का वायदा किया है। सफ़ीदों में अगर लोग हिम्मत करेंगे तो वहां भी बन सकता है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने इस्पताल की बात की। इस वाक्त तो हमारे पास फंडज की कमी है लेकिन मै कहना चाहती हूं कि हम कोशिश कर रहे है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन सोशल सर्विसिज के लिए जैसे हस्पताल है और दवाईयां आदि है, दे सकेगे देगे। पिछले साल सप्लिमेंटरी ऐस्टिमेंटस में ऐगजैक्ट फिगर तो मुझ याद नहीं परन्तु लाखों रूपया दिया था।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: जो 2 लाख 30 हफ़ार सफ़ीदों के लिए दिया था उसका पता ही नहीं लग रहा कि कहां है।

श्रीमती प्रभा जैन: तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब चूंकि कोई विशिष्ट बात कहने वाली नहीं है इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगी कि इस ऐप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once:

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Schedule

Deputy Speaker: Question is-

The Schedule stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I bet to move-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

**THE PUBLIC WAKES (EXTENSION OF LIMITATION)
HARYANA AMENDMENT BILL**

**THE PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION)
HARYANA AMENDMENT BILL, 1971**

Health Minister (Sh. Khurshed Ahmed): Madam, I bet to introduce the Public wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill, 1971

Sh. Khurshed Ahmed: Madam, I also beg to move-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Sub clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिब, मै क्लाज़ 2 के ऊपर बोलना चाहता हूँ। इसमें बात यह है कि इसक्लाज़ में इन्होंने वर्ष 70 के बजाय 71 कर दिया है इसमें मै एक सजेशन देना चाहता हूँ। वक्फ प्रोपर्टीज के बहुत से केसिटज कोर्टस के अन्दर चल रहे है। इस ऐक्ट के मुताबिक यह है कि

1947 के बाद के जो कब्जे हैं वे बेदखल हो जायेंगे और उसके पहले के जो हैं वे बेदखल नहीं सकते। वक्फ ऐक्ट के जब वे कोर्ट में जाते हैं तब उनको इस बात को साबित करने के लिए गवाही नहीं मिलती है कि यह कब्जा बाद का है या पहले का है। जो टैनेन्ट या मुजारा होता है वह कहता है कि मैं तो पाकिस्तान से सन 45 में आ गया था या 47 में आ गया था। तो इस ऐक्ट की सन् 71 तक अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं यह तो ठीक है। लज्जेकिन उन केसिज का भी कुछ इन्तजाम होना चाहिए जिन को दो-चार गवाह देने पर जज भूमि अलाट कर देता है। पहले जो कब्जे नाजायज हैं इसका भी ख्याल होना चाहिए। उनको भी बेदखल करने की इन्तजाम करना चाहिए।

श्री खुरशीद अहमद: जहां तक ऐविडेंस की बात है उसके लिए ऐक्ट में डिटेल्ड प्रोविजन है। इसमें तो लिमिटेशन बढ़ाने का सवाल है। यही मेरी रिक्वेस्ट है।

Deputy Speaker: Question is

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Sh. Khurshed Ahmed: Madam, I beg to move-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be passed.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया जहां तक अवधि बढ़ाने का सवाल है इसमें मेरी कोई दो राय नहीं हो सकती। एक बात जरूर है कि इतना अर्सा हो गया है लेकिन वह जायदार जो किसी धर्म स्थान के लिए हो उसका कब्जा नहीं छोड़ा जाता है या कोई दखल नहीं दिया गया है, इसका भी कोई कारण हो सकता है? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए। बहुत सारी बातें और कहनिया वक्फ जयदाद के बारे में सुनी जाती हैं वे सही भी हो सकती हैं। और गलत भी हो सकती हैं लेकिन एक बात जिसमें हम सहमत हो सकते हैं वह यह है कि धर्म स्थानों की कोई चीज हो उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसके ऊपर धक्का नहीं होना चाहिए और जहां धक्का हो रहा है उसका इन्तजाम इतने सालों से

क्यों नहीं हो पाया है? इसका कारण क्या यह है कि जो इन्तजाम करने वाला है वे उनसे मिले हुए है, इस कारण से उनका बिजा नहीं मिला या कोई अन्य कारण है? इस विषय में जो भी कारण हो वे सदन की जानकारी के लिए मंत्री महोदय दें। यहां जो अवधि मांगी जा रही है वह केवल एक साल के लिए मांगी जा रही है। आज सन् 47 को 23 वर्ष को गये है। अब तक ये झगड़े क्यों नहीं खत्म हुए? ये झगड़े तभी खत्म हो सकते हैं जब दोनों चीजों का पता चले कि कहां पर क्या खराबी है? कौन कौन इसके पीछे है? जिनके जिम्मे इनका संरक्षण लगाया हुआ है क्या वे गड़बड़ी कर रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति। इसलिए मैं मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि यह सदन जब भी आगे बैठे हैं वे इस सिलसिले में ए स्टेटमेंट दे ओर बताये कि कौन कौन ऐसी जायदादे हैं जिनपर दूसरे आदमियों ने कब्जा किया हुआ है और सरकार क्यों नहीं अब तक कब्जा ले सकी?

उपाध्यक्ष: आप स्टेटमेंट देंगे?

श्री खुरशीद अहमद: मैम्बर महोदय ने जो कुछ तजवीज दी है वह बहुत अच्छी है। इसके बारे में जो कुछ भी कर सकेंगे करने की कोशिश की जायेगी।

THE PUNJAB URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX
(HARYANA AMENDMENT) BILL 1971.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Madam, I beg to introduce the Punjab Urban Immovable property Tax (Haryana Amendment Bill, 1971)

Madam, I also beg to move-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment Bill) be taken into consideration.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती है कि इस सदन के अन्दर हमारे राज्यपाल महोदया ने अपने बजट स्पीच के अन्दर कोई 11 करोड़ रुपये का घाटा दिखलाया। उन्होंने यह भी कहा कि दो करोड़ रुपया तो इधर उधर से बचत के तौर पर आ जायेगा लेकिन नौ करोड़ रुपये का घाटा जरूर रहेगा। इन्होंने अपनी बजट स्पीच में या गवर्नर साहब के अभिभाषण में कोई इशारा नहीं किया कि टैक्स लगने चाहिए। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि जो अैक्स खत्म होने जा रहा है उसकी अवधि फिर से बढ़ाने जा रहे हैं। इस बिल के विषय में भी जिक्र गवर्नर ऐड्रेस में करना चाहिए था। जब एक टैक्स कुछ अवधि के लिए लगा है हमेशा के लिए नहीं तो फिर क्यों आसकी अवधि बढ़ाई जा रही है? इन्होंने उसमें लिखा है कि यह इसलिए लगाया जा रहा है कि कुछ खास हालात की वजह से और खास अवधि के लिए लगा है अब ये हर साल उसकी अवधि बढ़ाते

जाते हैं मगर उसका जिक्र कही नहीं आता कि इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। यह बिल तो ऐसा जिस हम मान बैठे हैं और इन्होंने सोचा कि इसको तो हम वैसे ही बिना विचार—विमर्श किये ही पास कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदया, यह ठीक है कि ऐसे ही देहात की सम्पत्ति के बारे में पिछले सदन में एक बिल आया था। पिछले साल भी बिल आया था उसमें हमने कई साल की अवधि बढ़ा दी थी अर्थात् चार या पांच साल की थी। अब भी शायद उसी नुक्ते पर यह जो टैक्स लगाया जा रहा है। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। पहजले तो कहना कि हम डिसक्रिमिनेशन हटा रहे हैं। और फिर टैक्स बड़े एलान करके लगाये जाते हैं गवर्नर साहब के अभिभाषण में, राष्ट्रति के अभिभाषण में कहा जाता है है या वित्त मंत्री जी अब अपनी स्पीच करते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि तमाम प्रदेश और देश इस टैक्सेशन के लिए तैयार हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने प्रदेश की तरक्की के लिए पैसा चाहिए और तरक्की के लिए टैक्स लगाये ही जाते हैं। लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर, डेमोक्रेटिक संस्थाओं के अन्दर जा ढंग होते हैं उसी ढंग से हमें टैक्स लगाने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कभी एक बिल आ गया, फिर दूसरा आ गया। यह कोई अच्छा तरीका नहीं। अभी शायद एक बिल और आया है 42 ट्यूबवैलों के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब गवर्नर साहब का अभिभाषण हो या वित्त मंत्री महोदया की तकरीर हो उसमें इसके

विषय में जिक्र आना चाहिए ताकि सदन के सदस्य उस पर अपने विचार देने के लिए तैयार हो कर आये। जिस भाई की जो भी राय हो वह सोच-विचार कर दे। जब तक सिी चीज को पढ़ा ही न हो उसके विषय में मैम्बर अपनी क्या राय दे सकते है? मैम्बर कम से कम पैरेंट ऐक्ट को देख कर आये कि उस एक्ट से जो पैसा आया है उसका ठीक प्रकार से प्रयाग हुए है या नही।

उपाध्यक्ष महोदया, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो अवश्य बन गयी है। परन्तु मुणे मालूम नही क्या कारण है जससे हमारे प्रदेश के लिए यूनिवर्सिटी एक कहानी बन गई है कौन उसके कसूरवार है यह तो मुझको मालूम नही क्योंकि मै तो न एजूकेशनिस्ट हूं और ही स्टूडैन्ट हूं इसलिए मुझ को बहुत ज्यादा इलम नही है लेकिन एक बात जरूर है कि आये दिन हम सुनते रहते है। कि आज वहां यहा हो गया और आज वहां यह भी हो गया। बहन चन्द्रावती जी और मुझ को वहां जाने का एक बार हाल ही में मौका मिला। हम कुरुक्षेत्र यूनिर्सिटी गये थे हमने समझा कि खाने पीने की कैन्टीन है, वहां खाना ख लेगे। खुश किस्मती समझिये या कुछ और समझिये वह दिन ऐसाथा जिस दिन विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति का भाषण हुआ। जिस वक्त हम शाम हो पहुंचे मैने पूछा कैन्टीन कहां है? जब एक दोस्त का नाम पूछा, उसका घर पूछता तो हमरे से पूछने लगे कि क्या आप चुनाव के सिलसिले में ओय हैत्र मैनक कहा हां इसी सिलसिले में आये है। किसके लिएये आप किस को चाहते है? जिस ढंग से उन्होन बात

की थी उसको हमने बड़ी गम्भीरता से सोचना है। वह बात मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वह एक अच्छी बात नहीं है। ने हमारे लिये अच्छी है न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अच्छी है। विश्वविद्यालय में शान से विद्यार्थियों के माता-पिता उनके लिये काफी पैसा खर्च करते हैं ताकि वे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसलिये बनाया गया था क्योंकि हम सब को गिला था कि पंजाब में यूनिवर्सिटी बनी है हरियाणा के अन्दर यूनिवर्सिटी नहीं है। इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पीछे एक बहुत बड़ी भावना थी। कुरुक्षेत्र, जहां महाराज कृष्ण ने गीता का प्रवचन दिया, हिन्दू धर्म की संस्कृति का पुण्य और पूज्य स्थान है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे याद है उस वक्त जो पालियामेंट के स्पीकर थे श्री आयंगर वे हमारे साथ आये और उनके साथ कई मैबर औ भी आये। मैं उस वक्त लोकसभा में था। उस वक्त उनहोने हमारी मदद की थी, क्योंकि उस वक्त जो शिक्षा मंत्री हिन्दूस्तान की सरकार के थे वे राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होने कहा हमारे प्लान के अन्दर कोई नयी यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत नहीं। उस समय पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों थे। उन्होने कहा हमने कुरुक्षेत्र के अन्दर यूनिवर्सिटी बनानी है ताकि वहां एक अच्छा वायुमंडल पैदा हो सके। आयंगर महोदय का यह ख्याल था कि यह संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनानी वहिये और हिन्दु सभ्यता के लिये वहां पर जानकारी दी जाये। उसके लिए खास सब्जैक्ट हो। उपाध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए एक बड्डी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी हमारे यहां कोई है नहीं,

फिर यह यूनिवर्सिटी एक अहम और पूज्य स्थान पर है, एक बहुत बड़ा ख्याल रख कर इसको कायम किया गया था। वह न तो संस्कृत यूनिवर्सिटी बन सकी, न हिन्दू सम्भ्यता बढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी बन सकी। इसकी अब हालत यह है कि वहां झगड़े होते रहते हैं अध्यापकगण और विद्यार्थियों का वह एक लड़ाई और युद्ध का स्थान बन गया है। कुरुक्षेत्र वैसे स्थान तो ऐसा ही है लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।

श्री के. एल. पोसवाल: वह हर यूनिवर्सिटी में हुआ है।

चौधरी रणबीर सिंह: इनको ज्यादा इल्म है क्योंकि यह गृह मंत्री है इसलिये सारे हिन्दूस्तान की बात ये बात सकते हैं। वह भी वक्त था जब विद्यार्थी अध्यापकगण के ऊपर बड़ी श्रद्धा रखते थे और हिन्दूस्तान की आजादी के बाद यह भी वक्त आया।

उपाध्यक्षा: मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा कि पहले बिल पर दस दस मिनट रखे थे उतना ही टाइम इस बिल पर बोलने के लिये रखा जाये।

चौधरी रणबीर सिंह: मेरी गुजारिश है कि बिजनै ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई हैं हम तो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का काम है कि हर बिल पर कितने समय तक बोलना है आप नई प्रणाली क्यों शुरू कर रहे हैं? तो मैं आपसे प्रार्थना और कहूंगा कि अगर कोई गलत बात कहे तो कहे तो उसको आपको आप रोकें क्योंकि ऐसा करना तो बहुत जरूरी

होता है। असल बात तो यह है कि हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है कि हम कानून सोच विचारक करके नहीं बातने है और फिर चैयर भी अगर हर कम बड़ी जल्दी से करना चाहते तो यह ठीक बात नहीं है।

उपाध्यक्षा: मैंने यह नहीं कहा कि आप कम समय लजो। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि हाउस के सामने और बिल भी पड़े है इसलिए मैंबर के बोलने की टाइम लिमिट होनी चाहिये। अगर वह हाउस चाहेगा तो टाइम ऐस्सटैड भी हो सकता है।

चौधरी रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, आप को बहुत बड़ा तजरूबा रहा है। 1937 में जबकि हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था उस वक्त भी आप पांजाब असैबली और कौंसिल की मैबर रही है। कभी इनती जल्दी नहीं हुई जितनी आ हो रही है। सरकार तो जल्दी कर सकती लेकिन आप ऐसी जल्दी करें यह मेरी समझ मे नहीं आता गुस्ताखी माफ हो मैं आपसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी की जाये। मैं चाहूंगा कि आप हमें इस बिल पर विचार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दे।

उपाध्यक्षा: मैं तो समय आप पर ही छोड़ दूंगी।

चौधरी रणबीर सिंह: मैडम, मैं तो आपसे एक अपील ही कर सकता हूँ और मैं भी आप पर समय छोड़ सकता हूँ आप मुझ जितना समय देना चाहे दे।

श्री के. एल. पोसवाल: रणबीर सिंह जी, आप चेयर को भी कह गये ।

चौधरी रणबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई हो और गृह मंत्री जी उसको साबित कर देंगे तो मैं आप दोनों से माफी मांग सकता हूँ। मैं इस सरकार की तरह नहीं कि सवाल का जवाब उल्टे लफ्जों में दूँ। यह तो सरकार का कायदा होता है कि यदि कोई गलती हो जाये तो माफी मांग ले। हमसे जब गलती हो जाती थी तो हम रिग्रैट लिख कर दिया करते थे, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करती। इसकी माफी मांगनी सीखनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैं कोई गलत शब्द इसतेमाल रि दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।

उपाध्यक्षा: जब मैं समझती हूँकि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है तो इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

चौधरी रणबीरसिंह: उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि कौन-कौन-सी बातें सुनी जाती हैं लोग कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम हरियाणा वालों का या हरियाणा के बच्चों का या हरियाणा के अध्यापकगण का इन्तजमा करेगे, मैं इस बात से इन्कार नहीं करूंगा। यह ठीक है कि देश के अन्दर कहीं कोई प्रादेशिक भावना पैदा नहो, इसके लिए हमेशा यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय में ऐ बात रखी गई कि हर प्रदेश के भाई इसमें

आये ताकि किसी प्रदेश में कोई ऐसी भावना न पैदा हो जाये कि देश के हितों के विरुद्ध हों लेकिन यहा जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमे यह माना जाता है है कि ज्यादा बच्चे और ज्यादा प्रशिक्षक उसी इलाके के हाते है जिस इलाके की वह यूनिवर्सिटी होती है। अगर हममें कोई गलती आ गई है तो हमें अपना कसूर मानना चाहिये। हम भी इस प्रदेश के हिस्सेदार है। छात्रों के असन्तोष को कैसे दुरुस्त करें यह सोचने की बात है। कोई लाठी से तो यह सिलसिला दुरुस्त हो नहीं सकता, समझौता कराने या उनको समझाने से कोई बात जरूर बन सकती है। उनके दिल को कोई चोट पहुंचती है। उस पर मरहम पट्टी करने से शायद हम दुरुस्त कर सके। वरना यह तो जबरबा कर रहे है वह काफी लम्बा होगा। इसके लिए आप जो पैसा रखेंगे मैं समझता हूँ कि उसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा। चाहे वह पैसा ये दे या कोई औद रदे। मैं सरकार से कहूंगा कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का जाब आज सवेरे यहां नात लिया गया तौ मैंने ऐतराज कियाथा कि वे यहां जवाब नहीं दे सकते, ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। जैसे उन्होने बताया अच्छा ही आदमी होगा जो इतना बड़ा तजरुबेकार है, और इससे अध्याप कभी तजरुबेकार ही होंगे लेकिन एक बात माननी होगी कि जो आन्तरिक झगड़े है उसको हम हल नहीं सके। उस झगड़े हो हल करने में हमें उनकी इमदाद करनी होगी और उनको हमारी इमदादर करनी होगी हयां पर एक ऐसी सद्भावना पैदा होनी चाहिये जिससे कि लोग यह समझते कि यह हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है। और इकी इज्जत हमारी अपनी इज्जत है।

यहां पर हमारे गृह मंत्री जी ने एक कही। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी बातें चली जिनका एक बहुत ही अजी सा इतिहास है। 1966 से पहले विश्वविद्यालय के अन्दर कोई झगड़े नहीं होते थे। यह झगड़े तब से शुरू हुए हैं जब से 1966 में बार कौंसिल की सिफारिश पर यह एलान किया गया कि 'ला' का कोर्स आगे सते तीन साल का हो गया है। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी जो कि हमारे नेता थे, ने मैट्रिकुलेशन का इम्तहान पास किया और उसके बाद वह विलायत से बैरिस्टर बन कर आ गये। इसके अलावा औरभी बहुत सारे नेता हैं जैसे सरदार बल्लभ भाई पटेल, जो कि ऐही ही बैरिस्टर अने। आज एक विद्यार्थी 13-14 साल लगा कर डिग्री लेता है और उसके बाद ला के लिये उसको तीन साल और लगाने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से यह झगड़ा ला पढ़ने वाले स्टुडेंट्स, जिनकी बहुत जिम्मेदारी है, जिनको हम सिखा रहे थे कि वह देश के अन्दर कानून की कैस रक्षा करेंगे, की तरफ से खड़ा हुआ है मेरा ख्याल है कि जो गलती सैटर ने की है, सरकार उसको बताये। सारे देश के अन्दर एक बवंडर उठा हुआ है। मैं मानता हूँ और इसका मुझे तजरबा भी है कि आज तक भी विश्वविद्यालयों में शान्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह सरकार शिक्षा में एक क्रांति पैदा कर दे। शिक्षा की क्रांति में हम बहुत पीछे हैं अमरीका के अन्दर, जैसे यहां किया जाता है। कि किताबों का रट्टा लगाया, और इम्तहान में लिखा दिया, नहीं किया जात। वहां तो किताब ले जाने का हुक्म है। वहा पर बड़े से बड़ा वकील और बड़े से बड़ा ऐडवोकेट जनरल जबानी नहीं बहस करता बल्कि

किताबों की पूरी मदद लेता है यहां पर क्या हाल है? यहां पर बच्चे कोई टैक्सट या कोइ रैफरैन्स बुम इम्तहानों मे नही ले सकते। यही नही और भर बहुत सारी बाते है, जिनको मै इस शिक्षा की कमिया समझता हूं। दूसरे देशों के अन्दर आप चल जाये। वहां इन्जीनियरों को या जो टैक्नीकल नौलेज वाले है, उनको कई काम करने सिखते है लेकिन यहा का तो ढंग ही निराला है। यहां का पढा हुआ इन्जीनिय प्रैक्टिकल तौर परकाम जानता ही नही हैं वह तो कागजी दुनिया मे रहता है। इसमें उसका कोई कसूर नही हैं हमारे देश के विश्वविद्यालयों मे पढ़ने वाले बच्चे अपनी हाथ में घी की कटोरी उठा कर चलना भी अपनी बेइज्जती समझते है। यहा कोई अच्छी बात नही हैं हमार तो गीरब आदमियों का देश है। विलायत में कोइ भी ऐसा देश नही जहां पर कि पढऱने वाल बच्चे कोई न कोई काम करत हौ। लेकिन यहां पर तो वह कोई चीज उठाकर चलना भी अपनी बेइज्जती समझते है, यह उनका कसूर नही है, यह हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसका कसूर है। जब तक हम अपनी परीक्षा की प्रणाली में सुधार नही करेंगे तक तक काम नही चलेगा। आखिर हमारे अध्यापकगण भी कही नह कही से ग्रैजुएट हो कर आये है, आज यदि हमारी सरकार और अध्याप गण के बीच मै लड़ाई चलती है तो इसका हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर रहे बच्चों पर, उनकी बुद्धि पर क्या असर होगा? मै सरकार से कहूंगा कि पैसा ही बहुत बड़ी चीज नही होती है यदि लोग पैसा कमायेगे, तो खर्चेगे भी। यदि प्रदेश के अन्दर आमदनी होगी तो वह विश्वविद्यालय के लिये

या दूसरे कामों में चर्चा भी होगी। पैसा और इकट्ठा करने की भी कोई बात नहीं लेकिन जब मैंने इन्हे कहा कि देहातों के साथ ज्यादाती हो रही है तो कहने लगे कि देहातों पर हम इसलिए इसलिए कम पैसा कर्चा कर है है क्योंकि हमें पैसा बचान है। मुझ इस बात का जरूर ख्याल है कि आज जो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर हमार खर्चा ओवर हैड बढ़ता ही जा रह है, और जिससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, उसको रोकना चाहिए। हम जितना पैसा ज्यादा से ज्यादा फजूलखर्च होने से रोकेगे उतना ही प्रदेश का हित होगा। अप उस पैसे को हरियाणा के बनाने पर लगाये। मुझ मालूम है कि सरकार को इस सब चीज क बावजूद पैसे की जरूरत है मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। मैंने सरकार से पिछली दफा भी कहा था और आज भी कहता हूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रसिद्धी या बदनामी हरियाणा की आनी सुनामी या बदनामी है। वहां शान्तिपूर्व ढंग से काम नहीं चला रहें वहां की अशान्ति में, चाहे पढ़ने वाले हो, शिक्षक या कोई और हो, कोई न कोई जिम्मेदार हैं वहां के झगड़े को शान्ति से निपटाने की जरूरत है उसमें हमारे प्रदेश की इज्जत बढ़ेगी। उसी में हमारे बच्चे जो वहां पढ़ते है और देखा देखी में ऐसी शिक्षा लेकर चले जिस पर कि उन्हे नहीं चलना चाहिए, उनका भला है। मैं यह नहीं मानता कि इस चीज का इलाज नहीं हो सकता है। यदि सरकार चाहे तो वह शान्ति से उन्हे समझाने के लिए ये चाहे कितनी ही पैसे खर्च करे, हमें काई एतराज नहीं परन्तु यह सरकार बहुत तेज है, इसमें बहुत तेजी है, काम में भी और दूसरी तितें मे भी। इनके व्यवहार और विचार में

बहुत तेजी है। वे हमारे अपने बच्चे हैं किसी गैर के बच्चे नहीं हैं। इस देश के कर्णधार हैं। घर के अन्दर अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसके सुधार के लिये हमें सब कुछ करना पड़ता है अगर हमारे विश्वविद्यालयों के बच्चों में कोई खराबी आ गयी है तो उनको हमें सुधारना चाहिए। उनमें असन्तोष के कुछ मोथलक कारण हैं और कई बसेकि बहूहात है उन पर सरकारको गौर करनी चाहिए। अगर इसके लिये इन्तहान की प्रणाली बदलने की जरूरत हो तो बदल दे। जैसे अमरीका के अन्द है चाहे वैसा कर दे और जिस तरह पहले रट्टा लगा कर बच्चे पा होतें वह खत्म कर दे। अगर अमरीका के अन्दर बगैर रट्टा लगाये काम चल सकता है तो यहां क्यों नहीं चल सकता? यदि अमरीका का पढ़ा हुआ यहां आ कर शिक्षा दे सकता है तो हिन्दुस्तान का पढ़ा हुआ बच्चा क्यों नहीं शिक्षा दे सकेगा। जो सिस्टम मैकाले यहा पर लगा गया, आज तक भी वही सिस्टम चल रहा है। उनका काम दूसरा था, उनका मुद्दा दूसरा था। हम आज कोई द्विभाषिये पैदा करने नहीं जा रहे हैं। हम तो इस देश के बनाने वाले पैदा करने जा रहे हैं। हमें सारा ढांचा और पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। हमारे गृह मंत्री जी हाउस से चले गये। आज हिन्दुस्तान की गृह मंत्री हमारी प्रधान मंत्री है ओर वह बहुत शक्तिशाली है लेकिन बच्चे बड़े शक्तिशाली होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे साथ पंजाब असैम्बली में एक मानयोग मैम्बर हुआ करते थे। वे कहं करते थे कि हम चाहे जो कुछ भ्ज़ी कर ले लकिन बच्चों पर काबू नहीं पा सकते। वे कहते कि बाप को हारने वाल बच्चे ही होते हैं.....

(विघ्न) बच्चे जब खराबी करते हैं, तो बाप को बड़ी शान्ति से सोचना पड़ता है, यदि घर में कोई तबदीली भी करने की जरूरत हो, तो हालात के मुताबिक वह करनी होती है। एक जमाना होता था जब कि मां बाप और बुजुर्गों के लिए बच्चों के दिलों में श्रद्धा होती थी लेकिन आज जमाना बदल गया है जो इस जमाने के साथ साथ नहीं बदलेगा, जमाना उनको अवश्व बदलेगा। हमारी तरफ एक कहावत है कि जिस वक्त जवान खवे से ऊपर दिखने लग जाता है तो उसको बराबर का समझा जाता है। और यदि वह कोई गलती करें तो उसे समझाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय के बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें उन्हें समझा कर ठीक रास्ते पर चालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके स्थान पर हम यह मानें कि हमारे पास शक्ति है हम उन्हें कुचल देंगे ता यह गलतफहमी होगी अंग्रेजों को भी बड़ा हौसला था, उनके राजय में सूरज भी नहीं छिप्ता था। लोग यह समझते थे कि अंग्रेज कुचल कर रख देंगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिपाही तैयार किए। हमारे खन साहिब भी उन्ही सिपाहियों में से है। मेरे खिलाफ जबान से कटु हो जाएंगे लेकिन हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं तो अहिंसा की शक्ति से हमने अंग्रेज की शक्ति को हराया था आज जो लोग यह समझते हैं कि हम शक्ति से किसी को दबा देंगे, यह विचार ठीक नहीं है। बच्चों को शक्ति से नहीं दबाया जा सकता। बच्चों को प्यार से जीता जा सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे

पैसे की परवाह न करें। आए साल वही पुरानी कहानी वही बातें हने से कोई लाभ नहीं। वेसे तो कहते है कि हम कोई टैक्स नहीं लगाते लेकिन चुपचाप बढ़ाते रहे है। अब कोई अैक्स नहीं लगाया है लेकिन कुछ दिना बात कोई नोटिफिकेशन निकालकर बढ़ा देगे। कितनी फीस अब तक बढ़ा दी गई है।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन): चौधरी साहब कौनसी फीस?

चौधरी रणबीर सिंह: आप तो देख रही है कि मेरसा समय समाप्त होने जा रहा है मै सारी इन्फर्मेसन कि कौनसी फीस बढ़ी है जब बजट पास किया जाएगा उस समय दूंगा। मेरा तो अंत में इतना ही कहना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मे अगर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के झगड़े खत्म हो जाएं तो हमारे प्रदेश की जितनी इज्जत बढ़ेगी उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदो): डिप्टी स्पीकर साहिब, अरबन इम्मूवेबल प्रापर्टी टैक्स में जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसके सम्बन्ध में मै बताना चाहता हूं कि पिछला सैशन में वित्त मंत्री महेदया ने लैड रेवेन्यू पर 50 प्रतिशत सरचार्ज पांच साल के लिए बढ़ाया था और इस अमैन्डमेंट के जरिए एक साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। उस वक्त मेने इस बामें मे कहां था तो यह जवाब दिया गया था कि शहरों में प्रौपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स दोनों लगते है। हम दोनो को अमैलगमेंअ करके एक ही कर

देगे लेकिन वहां तो यह काययाब नहीं हुए। सुबह चीफ मिनिस्टर साहिब ने गवर्नर साहिब के ऐड्रेस के जवाब में बताया कि हरियाणा हिन्दुस्तान में पहली स्टेट है जिसने कई चीजों में बहुत तरक्की की है।

डिप्टी स्पीकर महोदया, हरियाणा में ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो अब कायम हुई है लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो उस वक्त कायम हुई थी। जब डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। यह विश्व उनके दिमाग की उपज थी और उन्होंने इसे संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से बनाना चाहा। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत की लड़ाई लड़ी गई और जहां गीता का उपदेश दिया गया उन्होंने वहां इस विश्वविद्यालय को कायम किया हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है। जो अपनी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए कोई सरचार्ज या ऐडिशनल टैक्स लगाए। यह सिर्फ हरियाणा में ही हो रहा है। जब ज्यायंट पंजाब था तो यह टैक्स शायद अरबन इन्फ्राम्बल प्रापर्टी पर था ओर जब हरियाणा बना तो इसको जारी रखा गया। अब इसे 1975 तक बढ़ाया जा रहा है, लोग इसके लिए टैक्स देगे। बजाए इसके कि इसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए आजकल इसका सैयासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है पिछले दिनों हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब गए थे और उन्होंने ऐजुकेशनिस्टों को धमकी दी थी उन्हें निकाल दिया जाएगा, इस तरकी बाते वहां पर की। इस बात का उन लोगों ने बहुत रामनाया और उन्होंने एक सैपरेट मीटिंग की और यह पास किया कि हमारे

साथ जो इस किसम का व्यवहार किया गया है वह बहुत बुरी बात है उसके साथ साथ वहां पर लड़कों भी एक रैजोल्यूशन पास किया क्योंकि ये वहां पर लड़कों को भी धमकी दे आए थे कि इनको निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहां पर स्टुडेंट्स यूनियन का प्रैजिडेंट था, वह रिसर्च का स्टुडेंट था। यह हरियाणा की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब्बल तो यहां रिसर्च के लिए कोई पैदा नहीं होता और अगर हाता है तो उसको तंग किया जाता है उस प्रैजिडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया और उसको जो रिसर्च स्कॉलरशिप मिलता था वह वापिस ले लिया और उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यह सियासत का एक अखाड़ा बना हुआ है। जितना पोलिटिकल इन्टर होगा या बाहर क आदमी जाएंगे उतनी ही ज्यादा गड़बड़ होगी। यूनिवर्सिटी एक फंक्शन होता है जिसको कनवोकेशन कहा जाता है। उस वक्त भी यही कोशिश होती है किसी ऐसे आदमी को बुलाया जाए जो लिटरेरी हो, हाई कोर्ट का जज हो या कोई डिस्टिग्विश्ड आदमी हो। पोलिटिकल इन्टरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। इसको अवाएड करना चाहिए और वहां पर जो शिक्षा है उसका ठीक ढंग से प्रबन्ध होना चाहिए।

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इसलिए स्ट्राइक है क्योंकि वहां पर उनको खाना अच्छा नहीं मिलता है। वहां पर जो वार्डर लगे हुए वे पैसा लेते हैं, इसलिए लड़कों को अच्छा खाना नहीं मिलता। आखिरकार वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज के लड़के हैं, वे अपने घर

पर भी अच्छा खाना खाते हैं। वहां पर एक अलग से इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूशन है उसके अन्दर खाना बहुत अच्छा दिया जाता है। वहां पर ला के भी लड़के पढ़ते हैं। जब उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ला एंड आर्डर की पोजीशन भी वहां खराब होती है और ला एंड आर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उनको चाहिए कि शुरू से ही उसका ठीक इन्तजाम करें और वहां के वाईस चांसलर को कहें कि जो खाने के बारे में शिकायत है उसको ठीक करें। इसएिल मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो इस यूनिवर्सिटी के लिए सैप्रेट टैक्सेशन बढ़ करनी चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ग्रांट्स वगैरह देनी चाहिए। यहां पर उन्होंने बताया था कि हम और नए टैक्स नहीं लगाएंगे लेकिन आज तीन चार किस्म के टैक्स आहिस्ता आहिस्ता से ले आए हैं तो मैं समझता हूँ कि यह लोगों की आंखों में धूल डालने वाली बात है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर टैक्स लगाया भी जाता है तो जो लोगों ने पैसा वसूल किया जाए उस पर जायज इस्तेमाल होना चाहिए, वह रूपया अगर लड़कों को तालीम के लिए सही तरीके से खर्चा जाए तो हमें कोई एतरज नहीं लेकिन उस में भी पौलिटिक्स लजाने की कोशिश की जाती है। हमारे हरियाणा में यह केवल एक यूनिवर्सिटी है कहने को ये कहते हैं कि हम ऐड दे रहे हैं लेकिन इधर इस ऐक्ट के जरिए पैसा ले रहे हैं और उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करना है। यह कोई ग्रांट नहीं है और न ही ऐड है जब यह रूपया लोगों पर टैक्स लगा कर यूनिवर्सिटी को जाता है और यह ने ऐड है और नहीं ग्रांट है

तो फिर यूनिवर्सिटी के अन्दर यह भावना पैदान नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने कोई बात गवर्नमेंट की मन्शा के मुताबिक न की तो हमारी ऐड या ग्रांट बंद हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पैसे को नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि लोगो पर टैक्स लगाने की बताए गवर्नमेंट को अपने बजट से यूनिवर्सिटी को मदद देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इन्होंने वहां पर वातावरण खराब यिका है वहा कोई शोभा बढ़ाने वाली बात नहीं है। वहां पर जो रिसर्च स्टुडेंट की रिजस्ट्रेशन कैंसल करवाई है और उसका स्कालरशिप बंद करवाया है वह उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए और उसकी स्टडी कन्टिन्यू करवाई जाए। मैं जाती तौर पर उस लड़के का वाकिफ नहीं हूँ और नह ही वह मेरी जात बिरादरी का है ओर नह ही मेरी कांस्टिच्वेंसी का है लेकिन चूंकि वह हरियाणा का लड़का है इसएिल मैं कहता हूँ कि उसको हायर एजुकेशन का मौका दिया जाना चाहिए और विकिटमाईज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वह कल को दुनिया में चमके और हरियाणा का नाम रोशन करे। बस इतना कह कर मैं बैठता हूँ।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी रणबीर सिंह जी ने और सिगोल साहब ने अपनी स्पीचों में झा बात पर जोर दिया है कि जो बजट प्रपोजल्ज है उनका जिक्र बजट स्पीच में आना चाहिए था। मैं निदेदन करना चाहती हूँ कि हम को कतन ऐसा करने में गुरेज नहीं था। हम

बजट सेशन में ही बिल को लागू है क्योंकि पिछली दफा सन् 1971 तक का बिल पास हुआ था, अब हमने उसको 1975 तक का किया है पिछली दफा मैम्बरों को यह शिकायत थी लैंड रैवन्यू पर सरचार्ज लगाया गया है। ओर प्रापर्टी टैक्स नहीं लगाया गया। मैंने उस वक्त भी कहा थाकि सरकार ने हाउस टैक्स ओर प्रापर्टी टैक्स को अमैलगमेंट करने के लिए कमेटी बनाई हैं उस कमेटी की रिपोर्ट अब सरकार के पास आ गई है, जल्दी ही सरकार उस पर निर्णय लेगी और उसक पर अमल किया जाएगा। इस बिल पर बोलते हुए अधिकतर बातचीत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारमें की गई है और यह कहा गया है कि उसको बजट में से रकम देनी चाहिए। मैं उन मैबर साहिबान को यह बताना चाहती हूं कि यह सरचार्ज जो है यह हमारी सरकार नह नहीं लगाया, यह तो राव साहिब ने लगाया था और वह पुराना ही चला आ रहा है। इसएिल जो चीज पुरानी चली आ रही है। उसको बजट में लाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बत यह है कि इस विश्वविद्यालय का सारा खर्चा केवल इसी में से ही पूरा नहीं होता। पिछली दफा जब हमने बजट पास कियाथा तो उसे से हम ने 80 लाख रूपए के करीब दिए थे और जहां तक इस टैक्स का ताल्लुक है यह भी कंसौलिडेटेड फण्ड में जाता है ओर बाद में हम उनको देते है। इसके इलावा यहां पर यह काह गया कि यह संस्कृत विद्यालय होनी चाहिए थी क्योंकि यहां पर महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था ओर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझती हूं कि आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का

संचालन हो रहा है वह ठीक है। आज के युग में अगर हम दूसरी विद्या से अपने छात्रों को महरूम रखेंगे तो वह इस सायंस के युग में दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करेगा। महाभारत के जमाने में आप जानते हैं कि साइंस का बड़ा जोर था और हम चाहते हैं कि वैसा ही अब भी वहां पर होना चाहिए। जहां तक डिप्लोमिया वगैरा की बात है आजकल सभी जगहों पर कुछ यूनिवर्सिटीज में हो रहा है वहां सभीको मालूम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रिजेंट वाइस चांसलर के आने से वहां पर वातावरण काफी सुधरा है। बाकी सरकार का मन्शा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से उसमें पौलिटिक्स को रखा जाए। इस बिल में कोई खास बात नहीं थी। इसमें सिर्फ दो प्रपोजल्ज हैं। एक तो 1971 से इसको 1975 तक किया गया और दूसरी बात यह है कि जो एक दो एरिया में हमारी वैल्युएशन की मियाद है वह मार्च में खत्म होने वाली थी, उसके लिए चूंकि समय लगता है इसलिए हमने तीन साल का वक्फा मांगा है। हम प्रोपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को रैशनेलाईज करने जा रहे हैं, इसलिए अगर हम पहले वैल्युएशन लिस्टस तैयार कर लेंगे तो वह बाद में हमको फिर चेंज करनी पड़ेगी और हमारी पहली लेबर सारी जाया जाएगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ने मियाद मांगी है ताकि वैल्युएशन लिस्टस ठीक तरह से बनाई जा सकें। इन दो बातों के लिए हमने यह बिल पेश किया है। हाउस को मैं निवेदन करूंगी कि इसको पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration

The motion was carried

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB MOTOR VEHICLES TAXATION (HARYANA
AMENDMENT) BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Madam, I bet to introduce the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971.

Madam, I also beg to move-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

THE PUNJAB MOTOR VEHICLES TAXATION (HARYANA
AMENDMENT) BILL

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने राज्यपाल महोदय के

धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए बताया था कि वह हरियाणा की 80.02 फीसदी ट्रांसपोर्ट नेशनेलाइज कर चुके हैं और 31 मार्च तक और भी करे देगे और शायद थोड़े बहुत रूटस ही रह जायेगे जहां इनकी मोटरे नही चलेगी। इन हालात में मेरी समझ में नही आता है कि इस बिल के लाने की क्या जरूरत थी ओर इससे क्या फायदा होगा? यह तो एक खाता का पैसा दूसरे खाता मे लेने देने की बात ही होगी और यह सिर्फ पेपर ट्रांजेक्शन होगी। यह तो बिल का हौआ बना कर ख्वामखाह प्राईवेज औप्रटर्ज में, जो चंद रह गये है ओर वे भी मार्च के बाद इनके कहने के मुताबिक खत्म होने जा रहे है, रिजैटमेंट पैदा कर रहे ळ। इससे स्टेट को कोई फायदा भी नही होने वाला है क्योंकि एक तरह से वह बिल सिर्फ दो तीन महीनों के लिये है और उसे बार सारी ट्रांसपोर्ट इनकी ही हो जानी है। या त्ते यह बात है कि इनके दिल में ऐसी कोइ चीज है कि कुछ एक प्राईवेट ट्रांसपोर्ट वालों को लाइसैस देकर उनके रूटस ऐक्सटैड करना चाहता है और अगर यह बात नही है तो इस बिल को कोई फायदा नही है क्योंकि इस टैक्स से सारी इनकम स्टेट फंड से ही आयेगी और स्टेट के फंड में ही जायेगी और सिर्फ कागजी कार्यवाही ही बढ़ेगी। इन हालात में मै समझता हूं कि इस बिल की कोई जरूरत नही है।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो यह बिल बड़ा मासूम या मालूम देता है लेकिन इससे जितना

आज टैक्स है उससे दुगना हम करने जा रहे है। हमारी गाड़ियां आज बहुत सारी सरकारी हो गई है और रहती है वे भी जैसे ये कहते है सरकारी होने जा रही है। मुझे मालूम देता है कि इस बिल पर काफी सोच विचार की जरूरत है।.....

श्री बंसी लाल: चौधरी साहब ज्यादा लम्बी सोच न सोचा करें यह इतनी सोच की बात नहीं है। (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह: यह मैंने इस लिये कहा और मेरी परेशानी इसएल है कि आज हमारी गाड़िया जम्मू तक जाती है, जयपुर और देहली जाती है। अगर हमने टैक्स बढ़ा दिया तो जो कही थोड़ी बहुत प्राइवेट गाड़िया होगी दूसरी स्टेट्स भी टैक्स बढ़ा देगे और.....

श्री बंसी लाल: चौधरी साहब टोकन टैक्स दूसरी स्टेट्स में नहीं दिया जाता। अपनी स्टेट की गाड़ियां जब टोकन टैक्स अपने हां दे देती है तो दूसरी स्टेट वाले क्लेम नहीं कर सकते है।

चौधरी रणबीर सिंह: यह तो ठीक है लेकिन इसमें एक और बात भी और वह यह है कि पैप्सू रोड कारपोरेशन में हम हिस्सेदार है और उनका सारा ही टोकन टैक्स पंजाब वाले ही ले रहे है क्योंकि वह सारी गाड़ियां वहा ही रजिस्टर कराते है। सह तो अच्छी बात है कि जिस बात से मै डरता था उस बारें में उन्होने कह दिया कि वह रीएक्शन नहीं होगा जिसका मुझे खदशा था, लेकिन अगर फर्ज किया कल को कोई आपस में समझौता

ऐसा हो जाये कि जो गाड़िया चलत है दूसरे प्रदेशों की, जिनको हमारे प्रदेश में चलने की हक है कानूनी तौर पर और हम कहे कि तब चलने देंगे अगर हमारे यहां कुछ परसैटेज रजिस्टर कराओं तो.....

Sh. Bansi Lal: If any such thing happens, it will be reciprocal.

चौधरी रणबीर सिंह: मैं वही बात कहने लगा था। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश की चंद गाड़ियों की बात हो तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इससे इन्टरस्टेट झगड़ा बाद में खड़ा हो तो यह सोचने की बात है। ऐनऐब्लिंग अख्तियारात देने में हमें कोई इतराज नहीं लेकिन शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त यह ध्यान रखा जाये कि कोई आपस में झगड़ा न हो जाये और बजाये फायदा के घाआ होना शुरू हो जाये।

Sh. Bansi Lal: There will be no iner-state dispute.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(HARYANA AMENDMENT) BILL.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimat Om Prabha Jain: Madam, I bet to move-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxation (Haryana
Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxation (Haryana
Amendment) Bill be passed

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Madam, I request that the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971, be taken up first.

Deputy Speaker: All right.

Sh. Om Prabha Jain: Madam, I beg to introduce the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971

Madam, I also bet to move-

That the Punjab Passengers and Goods. Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Passengers and Goods Taxatio (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Sh. Bansi Lal: There will be no iner-state dispute.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(HARYANA AMENDMENT) BILL.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimat Om Prabha Jain: Madam, I bet to move-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be passed

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Madam, I request that the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971, be taken up first.

Deputy Speaker: All right.

Sh. Om Prabha Jain: Madam, I beg to introduce the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971

Madam, I also bet to move-

That the Punjab Passengers and Goods. Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Passengers and Goods Taxatio (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो भिक्षावृत्ति बंद करने के बारमें में बिल हमारे सामने आया है इसके लिए सचमुच सरकार बधाई की पात्र है और मैं समझती हूं कि यह अच्छी बात की गई है। मुझे इस बात की भी खुशी है। कि चाहे हमारी स्टेट छोटी है लेकिन यह काम हमारी स्टेट से शुरू हुआ। इसके साथ साथ में यह कहना चाहती हूं कि गलियों की भिक्षा से लेकर हम आय यू.एन.ओ. तक भीख मांगने चले गये है। मुझ यार आता है कि जब भी कभी यहां देश में अकाल पड़ा तो विदेशों में वहां के छोटै छोटे बच्चों ने भी अपना पौकेट मनी बचा बचा कर हमारे लिये भेजा कि हिन्दुस्तान के लोग भूखे मर रहे है। मैं समझती हूं कि हय भी बैगरी है। उपाध्यक्ष महोदया, बिहार में अकाल पड़ा तो लोग भीख मांगते थ। भीख मांगने के एिल धर्म भी छोड़ देते थे और बहुत सारे क्रिशचियन बन गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि भीख मांगना हमारे संस्कार में है। पहले

लोग जनेऊ के नाम पर गांवों में भीख मांगते थे। बोद्धीजम और जैनीजम में भिक्षा मांगने की संस्थाए है जो हमें संस्कार के रूा में का कर रही है। हो सकता है संस्कार में भिक्षा वृत्ति होने के कारण ही ये संस्थाए संसार के नक्शे पर छाई हुई है। संसार में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां पर ये मांगते न हो। मैं चाहती हूं कि हम सारे हिन्दुसतन मे इस भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिए इस तरह का कोइ ऐक्ट लाएं ताकि हमारे देश की शोहरत दुनिया में कायम हो। इस वृत्ति के कारण हमारे देश की शोहरत बहुत नीचे हो गई है। आपने दखा होगा, जापान और जर्मनी जैसे मुल्के के दो दो टुकड़े हो गये, जिनकी आबादी का एक चौथाई हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन उन्होंने भिक्षा-वृत्ति को नहीं अपनाया जिस तरह हमारे देश में अपनाया गया है मैं तो चन्दा मांगने के भी खिलाफ हूं। यह भी एक प्रकार की भिक्षा ही है। गरीब आदमी भिक्षा मांग लेता है और अमीर चंदा मांग लेता है। मैं समझती हूं कि चन्दे के नाम पर देश में इतनी भारी कुदरप्शन हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि कौनेडा में चुनाव लड़ने के लिए सरकार की तरफ से उम्मीदवारों का पैसे मिल जाते है लेकिन वे चन्दा नहीं मांगते। यहां सेठ और शाहूकारों से चुनाव के लिए चन्दा मांगा जाता है। सेठ या शाहूकार अपनी जेब स चन्दा नहीं देता वह वास्तव में सरकारी खजाने से ही चन्दा देता हैं क्योंकि जब वे चन्दा देते है है तो इस चन्दे की बिना पर कई गुना फायदा उठाते है। जो कि लोगों के खून पसीने की कर्मी होती है। हमारे

एक मित्र है जो कह रहे थे मुझे 10 लाख रूपये का फायदा हाता है और उसमें से 10 हजार रूपया पौलिटिशियन्ज की जेब में कहा है जो शाहूकार की दे दें? वह सरकारी खजाने से आता है। फिर कहां जाता है कि कीमते बढ़ रही है, कीमतें क्यों नहीं बढ़ेगी? जिस व्यक्ति से चन्दा लेते हैं वह कीमते जरूर बढ़ाएगा। सरकार को इस चीज पर कोई न कोई चैक रखना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट कहता है कि तन्खा बढ़ा दो। जिस दिन तन्खा बढ़ती है। उसी दिन से कीमतें बढ़ जायेगी क्योंकि शाहूकार ने चन्दा देकर फायदा उठाना है। इस सभी चीजों का कारण यह है कि हमारे संस्कार में भिक्षा वृत्ति है। हम संकोच नहीं करते कि किस चीज का चंदा मांगते हैं। मैं आपको चर्खी गांव के एक जमींदार की बात बताती हूं। हमारी तरफ एक बार अकाल पड़ गया था। अकाल के कारण जमींदार के पास खाने की सामग्री खत्म हो गई। भीख मांगने की आदत नहीं थी। उसने भीख मांगने के लिए एक लाठी पर झोली बांध ली। जिस किसी के घर जाता था लाठी पर बंधी हुई झोली सामने कर देता था। इस तरह उसका गुजार कई साल तक होता रहा कई साल के बाद पंचायत हुई। पंचायत में उसको कहा गया कि अरे तू क्या बोलता है तू तो भीख मांगता था। उसने कहा—‘मैं लाठी के ठोर लेता था’। इसी तरह पौलिटिशियनों होता है, चन्दे के बहाने भीख लेते हैं। हमें इस कुर्र्शान को खत्म करना चाहिए। हम छोटे मुलाजमों को कहे हैं कि फलां आदमी ने रिश्वत ली है। इसलिए उसको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड तो कर दे है लेकिन यह नहीं देखते हैं कि यह वृत्ति कहां से पैदा होती है? इसका कारण

यह है कि हमारे सिस्टम में, संस्कार में भिक्षा वृत्ति आ गई है। चाहे इसको भिक्षा वृत्ति कहो, चाहे भीख कहो, चाहे चन्दा कहो और चाहे डोनेशन कहो, एक ही बात है। अगर सरकार चन्दा मांगने की वृत्ति को खत्म करने के लिए कोई ऐक्ट लाये तो मैं हरियाणा सरकार को बंधई दूंगी। अगर हमने मंहगाई बन्द करनी है, चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकना है, अडल्टैशन को रोकना है व्यापारियों को ईमानदार बनाना है, चोर-बाजारी को रोकना है तो इस चन्द्र रूपी भिक्षा को खत्म करने के लिए एक ऐक्ट लाना चाहिए, तभी कुरप्शन को दूर कर सकेगी। बिना ऐक्ट से ये चीजें बन्द नहीं हो सकती। हमें मालूम है कि सरकार बहुत काम कर रही है। लेकिन कुरप्शन की वजह से सूबे को आत्म निर्भर नहीं बना सकती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे एक उदाहरण याद आ गया है। किसी खाते पीते जमींदार के घर पांच छः बहू बेटे-बेटिया थी। उन सबन ने अलग अलग 'गांठी' करनी शुरू कर दी। कोई घर का अनाज बेचे, कोई बछड़ा बेच दे, जिसका जो जी चहो बेच कर पैसा अपनी गांठ में रख ले। उस घर में चाहे जितना अनाज पैदा हो, 10 हजार मन पैदा हो, उसका पता ही नहीं लगता था कि कहां जाता है। धीरे धीरे उस घर का दिवाला निकल गया यही हाल हामरी सरकार का है। जो भाई ऊपर बैठे हैं वे ही व्यक्तिगत गांठे बनाने लगे हुए हैं। गवर्नमेंट चाहे जितनी डवैल्पमेंट के काम कर दे, चाहे बिजली लगवा दे, चाहे कुछ कर दे, जा घर के बेटे-बेटियां की तरह ऊपर बैड़े हुए लोग हैं आपने व्यक्तिगत गांठे भरने में लगे हुए हैं वे हमारा दिवाला निकाल देगे, हमारे चरित्र

का दिवाला निकाल देगे। कोई भी आदमी महफूल नहीं रह सकता, किसी भी आदमी को कोई सिक्क्योरिटी नहीं कि वह चरित्रवाल रहे सके। यह जो बैगरी बिल अयाहै इसका क्रेडिट प्रभु सिंह जी को आना है क्योंकि यह उन्ही का महकमा है। अगर इसी तरफ चंदे लेने की वृत्ति खत्म करने के लिए बिल ले आएं तो हो सकता है कुछ लोगों की दुकान बन्द हो जायेगी जो चन्दा ले ले कर लखपति बने बैठे है। अगर ये लखपति खत्म हा जाएं तो देश में एक नई रिवायात हो जाएगी। यह देश के लिए नई बात होगी देश के लिए एक नये रास्ते का निर्माण होगा और सरकार की अच्छी शोहरत होगी। इन शब्दों के साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहब, चले गये है, अगर होते तो अच्छा होता क्योंकि मैं इस बात के लाने पर सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सूबेदार साहब को ता बेधाई नहीं दूंगा क्योंकि यह उनके अपने दिमाग की बात नहीं है। अगर इनके अपने दिमाग की बात होती तो मैं इन्हें बधाई देने के लिए तैयार होता। (सूबेदार प्रभु सिंह की तरफ से विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह ऐक्ट हरियाणा के लिए बड़ा जरूरी थी क्योंकि भीख मांगने की लानत बहुत ज्यादा फैल गई है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में मंगते बहुत ज्यादा थे। दिल्ली के बाजारों में इनकी लाईनों की लाईनें लगी रहती थी ओर जगह जगह भीख मांगते फिरते थे। बाहर से

जो फौरनर्ज आते थे वे इन मंगतों को इकट्ठा करके रीले बनाते थे और अपने मुल्क में लोगों को दिखाते थे ओर कहते थे कि जो पैसा हिन्दुस्तान का दिया जात है वह इन गरीबों पर नहीं बल्कि पार्टी प्रागेगण्डा के लिए इस्तेमाल होता है। नतीजा यह होता था कि बाहर से पैसा नहीं मिलता था। इस बिना पर कि इनके हमारे मुल्क की बेइज्जती होती है गवर्नमेंट ने दिल्ली में भीख मांगना बंद कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वे दिल्ली के चारों तरफ निकल गये और हरियाणा में दाखिल हो गये। आपने देखा होगा, अगर कभी अम्बाला कैंट के बस स्टैंड पर जाने का मौका मिला हो, कि कई मुस्टंडे बिल्कुल ठीक ठाक है, बड़ी अच्छी तरह से कमा कर खा सकते है, हाथ में डिब्बा लिए मांगते है और मुसाफिरो को तंग करते है। कल जब मै आया तो वहां पांच-छे खड़े थे बाकि पहले एक दो हुआ करते थे। इस बात को रोकने का जो विचार गवर्नमेंट ने किया यह एक अच्छी बात है लेकिन मै इसमें कुछ संशोधन देना चाहता हूं। सैक्शन 1 की क्लोज 3 में लिखा है:-

“(3) It shall come into force in any areas of the state, one such date or dates as the state Government may be notificatioj appoint in this behalf for that area.”

Wish that it should be delected and it should be read as:-

“(3) It shall come into force at once.”

जो लिखा हुआ है कि स्टेट के किसी हिस्से में नोटिफिकेशन के जरिए यह कानून पहले यू हो जाएगा और किसी हिस्से में बाद में होगा यह बात नहीं होनी चाहिए। यारी में इसे फौरन लागू कर देना चाहिए।

दूसरे यह जो कोर्ट की डैफिनिशन दी है कि:-

“(g) “ Court” means the court of the Judicial Magistrate on any class exercising criminal jurisdiction in the area in which this Act in force;”

उसके बाद यह दिया है कि पावर्ज कौन सी कोर्ट में वैस्ट करेंगी:-

4. (1) Where a person is brought before a court under section 3, the court shall make a summary inquiry in the prescribed manner as regards the allegation that he was found begging”.

प्राइमरी प्रोसीजर इन्होंने रखा है कि समरी प्रोसीजर के बाद कनक्विकशन हो जाए लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को समरी प्रोसोडिंग के अख्तियार नहीं होते। ये अख्तियार हाई कोर्ट से दिए जाते हैं और कुछ स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स को ही होते हैं जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। तो इसे अन्दर जो कोर्ट की डैफिनिशन दी गई है-

It Should be amended as :-

“Court” means the court of a Judicial Magistrate of any class having powers to decide it summarily by exercising criminal powers in the area in which this Act is in force.”

Then there is Clause 31, in which it is stated:-

“(1) The State Government may, by notification and subject to the condition of previous publication make rules for carrying out the purposes of the Act”.

इसमें 'में' के बजाय 'शैल' होना चाहिए। यह तो औबलिगेटरी होना चाहिए और इम्पीजिएटली ऐनफोर्स करके इस बीमारी को इस प्रदेश से हटाना चाहिए। आप देखें इनके पास न तो कोई कपड़ा होता है जिसे ये शरीर के ऊपर ले सकें और न रहने को कोई ठिकाना होता है। मगर फिर भी बड़बूटे मजे से रहते हैं और इन्हें कोई सर्दी महसूस नहीं होती जबकि हम लोग रजाई लेते हैं, नचे गदेल्ला होता है, ऊपर कभी कम्बल भी लेते हैं और फिर चार दीवारी के अन्दर होते हैं परन्तु फिर भी सर्दी महसूस करते हैं। इसका क्या कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि आदम बन जाती मगर यह आदत वाली बात नहीं। ये लोग सुलफा और शराब आदि पीते हैं और सारी की सारी रात नशे में काट जाते हैं। इस लिए इनको सर्दी महसूस नहीं होती। यह पैसा लेकर नाजायज इस्तेमाल करते हैं। इस बिल से एक तो यह बीमारी दूर होगी और दूसरे मांगने वालों को पता लगेगा कि वे मांग कर गुजारा नहीं कर सकते लेकिन उन्हें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। इससे हरामखोरी दूर होगी और ऐसा करके हमें अपने मुल्क की बड़ी भारी सेवा करेंगे। ट्रेजरी बैचिज से चन्द्रावती जी ने

दूसरी स्टेटों के बारे में बहुत कुछ कहा लेकिन मैं बातना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट के अन्दर भी बहुत बुरी हालत है। कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जो बाई प्रोफेशन मांग कर खाती हैं और दूसरी तरफ ध्यान नहीं देती। उनको इस बीमारी से बचाने के लिए था यह सिखाने के लिए हर आदमी को कमा कर खाना चाहिए तथा प्रदेश के लोगों की हालत सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी बिल है। मैं सूबेदार साहब को जो इस बिल का लाये बड़ा धन्यवाद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अमेंडमेंट मैंने दी है इसको एक दम बड़ी संख्ती के साथ सारी स्टेट में लागू करना चाहिए, उस पर ये गौर फरमायेगे।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल आया है इसको लाने के लिए वैसे तो मैं इस सरकार की तारीफ करता हूँ क्योंकि देश में भीख मांगने से बचनामी होती है। लेकिन इस बिल में कुछ तबदीली चाहता हूँ। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनमें हाई कोर्ट के जज भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, राजे महाराजे भी होते हैं, वे जब सन्यास लैते हैं, चौथी अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले गुरु मन्तर लैते हैं। कि पांच घरों में भिक्षा मांग कर रोटी खायेंगे। यह उनका एक नियम है। अभी मैं कुछ दिन पीछे हरिद्वारा गया था। एक बहुत अमीर आदमी था, करोड़पति आदमी था। उसके बेटे ने उसे कहा कि पिता जी आप यहां रह कर भजन करें सारा खर्चा मैं दूंगा लेकिन उसने कहा कि मुझे खर्चा वर्चा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो

पांच घरों में मांग कर रोटी खाऊंगा। इसी तरह की बाम मुझे मथुरा बृन्दावन में देखने को मिली। एक बहुत बड़ा आदमी इस्तीफा देकर वहा आया। उसकी घर वाली और लड़का भी उसे साथ थे। उन्होंने उससे कहा कि आप यहां भजन किया करना नौकर आपको रोटी बना दिया करेगो। मगर उसने भी उनकी बात नहीं मानी और खुद पांच दरवाजे से रोटी मांग कर खाता था। तो इस किस्म के बहुत से महात्मा लोग है जिनके ऊपर इस बिल के द्वारा पाबन्दी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इस तरह से मांग कर खाना उनका एक नियम है। वे समझते है कि जब तक वे इस तरह से मां गर नहीं खांयेगे तब तक उनका बड़प्पन कम नहीं हो सकेगा। कही ऐसा नह हो कि उन लोगो के भी मांगने न दिया जाए ओर वे अपना नियम पूरा न होने की वजह से बिना रोटी खाये ऐसे ही शरीर बदल जे। नियम हमेशा नियम होता है। कोई आदमी बिना नियम के चल नहीं सकता। कोई मोटर गाड़ी बिना नियम के नहीं चल सकती। कोई आदमी टाईम टेबल के बिना ठीक ढंग से चल नहीं सकता। यह सूर्य भी बिना नियम के नहीं चल सकता। इसलिए उन लोगों के कुछ नियम होते है वे लोग अपना घर बार सामान, धन दौलत सब कुछ त्याग कर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर बैठते है। और जब तक वे पांच घरों से रोटी मांग कर नहीं खाते तब तक उनको सन्यास नहीं मिलता।

कुछ आदमी मस्ती से भिक्षा मांगते है। उनका इन्तजाम जरूर होना चाहिए लकिन कुछ आदमी अंग-हीन होते है जैसे की

के टांग नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होता, किसी के आंख नहीं होती और उनके पास कोई चारा नहीं होता सिवाए इसके कि वे मांग कर खाएं, ऐसे लोगों का सरकार को कोई परमानैन्ट इन्तजाम नकर देना चाहिए ताकि उन्हें भी कानून से परेशानी का सामना न करना पड़े। (विधन) हमारी सरकार तो यह कर देगी मगर किसी और स्टेट ने अगर इसकी नकल करके बिल तो पास कर दिया मगर इस बात को ध्यान में न रखा जाए तो जो लोग बेकस है, बे-सहारा है, जनके टांग नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है वे मारे जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस बिल में कोई प्रोविजन करदे जिसके द्वारा यह देखना सरकार का फर्ज बन जाए कि आया ऐसे लोगों को दो टाईम रोटी मिल रही है। या नहीं, पहनने का कपड़ा मिल रहा है या नहीं, कहीं सर्दी में ही तो नहीं मर रहे। तो इस इस किस्म की बात इस कानून में जरूर होनी चाहिए क्यों कि यह कर्मा का फल होता है कि एक आदमी तो अच्छे घर में पैदा होता है, उसे बढ़िया रोटी खाने को मिलती है और बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलता है। मगर दूसरा आदमी लंगडा लूला होता है। एक दंड तो उसे कुदरत देती है और दूसरा दंड अगर सरकार दे दे तो बहुत बुरा होगा। क्योंकिजा कुदरत के सताये हुए वरुकि है, जो पिछली गड़बड़ों के सताये हुए है उन आदमियों के अगर रोटी के साधन खत्म हो जायेगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर इस किस्म की तबदीली आनी चाहिए कि जो आदमी ढोंग करे, या ढोंग बना कर मां गकर खाये, या काम करने

के डर से मांग कर खाये उनके ऊपर अवश्य ही पाबन्दी होनी चाहिए। इस प्रकार से तो जैसे हम वोट मांगने का कोई तरीका थोड़ा ही है अब बहिन जी अम्बाला से एम.एल.ए. बन कर आयी है ये वोट मांग कर ही बन कर आयी है। अगर हमने यह तरीका अपनाया तो कहीं की बात कहीं पहुँच जाएगी और इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमें उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए और सब को सोचन चाहिए। इससे तो उल्टा असर भी पड़ सकता है जो लोग साधु महात्माओं को अन्न देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, उनके लिए आश्रम बनाते हैं कहीं ऐसा न हो कि इस कानून से वे भी बन्द कर दिय जाऐ।

संसार में सब से महत्व की चीजें दो ही हैं। एक ध्यान और दूसरा भजन। गांधी जी की एक वाणी ने अंग्रेजों को देश से निकाला। इसलिए इसमें कुछ तबदीली लाने की जरूरत है। हमारे देश की भूमि ऋषियों की भूमि है, यह तपोभूमि है आज से नहीं पिछली सदियों से रही है। इस देश में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वे मांग कर खाते थे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को किसी कमेटीके पास भेजा जाये। वह इस पर विचार करके या जो कानून बनाने वाले हों उनको कहे कि इसमें तबदीली लायें। कहीं ऐसा न हो कि हम इस वकत कानून बना दें और उन गरीबों के विषय में किसी बात का खयाल न करें। डिप्टी स्पीकर साहिब, आपका पता है और आप तो बड़ी दयालु हैं। कि जो लोग मांग कर खाते हैं। उनमें ऐसी आदमी भी होते हैं जिनकी बड़ी

मजबूरियां होती है। हमारे जितनी भी पुराने ग्रन्थ है चाहे वह गीता है, रामायण है, महाभारत है उनको पढने से पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किये है है। उन्होंने देश के लोगों को बड़े अच्छे अच्छे विचार दिये, देश भावना पैदा की। हमारे देश के अन्दर सब से ज्यादा धर्म को ऊंचा स्थान दिया जाता है। और सबसे अधिक धर्म का ही प्रचार हैं हमारे ऋषि मुनियों ने केवल हमारे देश को ही रास्ता नहीं दिखाया है बलिक दूसरे देशों के अन्दर जा कर भी धर्म का प्रचार किया और अज्ञानता से लोगों को बचाया। इसी कारण से दूसरे देशों में हमारे ऋषि-मुनियों का आदर है।

उपाध्यक्षा: बिल भी पास करना है इसलिए आप कितना समय और लेगे?

चौधरी लाल सिंह: ज्यादासमय नहीं लेता अभी समाप्त करता हूं। आप जब हुक्म करेगी बैठ जाऊंगा परन्तु एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझ दस साल तक साधूओं के साथ रहने का अवसर मिला है। जैसा कि आपको भी पताहोगाऔर सदन के मरे दूसरें साथियों को भी मालूम होगा कि कई लागे पहले हाई कोर्ट और सुपीम कोर्ट के जज रहे लेकिन बाद में साधू और सन्यासी बने। इस लिए इस प्रकार के जो भी साधू है उनपर किसी भी प्रकार कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि महात्मा बनने पर ही पाबन्दी न लग जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपे जरिए हाउस को एक बात और बताना चाहता हूं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भीख मांगते हैं। देखने में आया है कि भीख वे इसलिए मांगते हैं कि उनके पास मांगने के सिवाए और कोई चारा नहीं है उनके विषय में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई न कोई प्रबन्ध करे। वैसे तो मैं इस बिल की सरहना करतहूँ और स्वागत करता हूँ लेकिन एक दो बातों के लिए इसमें तबदीली लाई जाये ताकि हमारे जा सही रास्ते हैं उनसे पीछे न हटें।

उपाध्यक्ष महोदया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया और साथ ही सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ऐसा बिल लाई लेकिन साथ ही साथ एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी है, जो मेहनत भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी चार आदमियों के पास एक चारपाई और एक रिजाई होती है। इसलिए मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि उनके लिए यह कपड़े ओर खाने का प्रबन्ध करे। जो भी मैंने इस बिल के लिए सुझाव सदन में पेश किए उनके विषय में सरकार विचार करके इस कानून में तबदीली लाये। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षा: हाउस से मैं यह जानना चाहूंगी कि कितने आनरेबल मैम्बर इस बिल पर बोलना चाहते हैं और हाउस का कितना टाईम ऐक्सटेन्ड किया जाये? क्योंकि बिल भी पास करने है ओर कुछ आनरेबल मैम्बरों को बोलने के लिए टाईम भी देना है

केवल आधा घंटा हमारे पास है क्या आधे घण्टे के लिए हाउस को ऐक्सटेन्ट कर दें।

कुछ आवाजे: ऐक्सटेन्ट तो न किया जाए मगर बोलने के लिए अब पांच पांच मिनट ही दिए जाएं ताकि टाईम से सारा काम खत्म हो जाए।

उपाध्यक्ष: बहुत अच्छा।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, आज हम यह बिल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए इस सदन में लाये है। इसके लिए हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के लोग भी धन्यवाद के पात्र है। आप जानती है आसे 23साल पहले जब यह देश आजाद हुआथा उस समय हमारे लाखों भाई पाकिस्तान से बेघर हो आये थे यानि पचास लाख से ज्यादा भाई बेघर हो कर आए थे। उनका बोझा सबसे अधिक पंजाब ओर हरियाणा ` लोगों पर पड़ा था। उन भाईयों में कुछ दूसरे प्रदेशों में भी गये लेकिन वे आज तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके है। जहां तक हमारे प्रदेश में भी गये थे लेकिन वे आज तक अपने पैरो पर खड़े नहीं हो सके है। जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है तकरीबन सभी भाई अच्छी तरह से सैटल हो गये है। उस वक्त ऐसी हालत भी आई जब जो बहादुर और हौसल वाले भाई थे, उन्होंने आजादी की खातिर वहां से अपने घरों को छोड़ा और इधर आये तथा अपने पैर जमा कर यहां आगे बढ़े। जो यहां के रहने वाले भाई थे

इन्होंने भी उनका सहयोग दिया जिससे इस प्रदेश के अन्दर ऐसी हालत पैदा हुई कि कहीं भी भिक्षावृत्ति न रही। यह बात तो बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश के लिए और हमारी सरकार के लिए जो ऐसा बिल ला रही है।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान दूसरी तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि कानून से भिक्षावृत्ति नहीं रूक सकती है क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो कि कानून पास करने पर भी बन्द नहीं होती जब तक कि उनके धन्ध को या उनका दिल को न बदला जाये। एक चीज आप देख ही रहे हैं कि आजकल समाज का रुझान दूसरी तरफ जा रहा है जो बिल्कुल गलत तरीके है, जैसे कि आप बंगाल प्रदेश के अन्दर देख रहे हैं। जो बेरोजगार है उनको भिक्षावृत्ति की आदत पड़ गयी है। कुछ को तो बेबस हो कर मांगना पड़ता है,.....क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वे भिक्षावृत्ति करते हैं। लेकिन अब लोगों का ध्यान उस तरफ से हट रहा है। दूसरी वृत्ति की तरफ आ रहा है। ऐसी वृत्ति इस देश के अन्दर नहीं होनी चाहिए क्योंकि जैसा समाजवाद हम लाना चाहते हैं। उस समाजवाद के अन्दर इसकी जगह नहीं है। उनका रुझाना भिक्षावृत्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसा कि सदन को पता है कि बैंक लूटे जाते हैं और दूसरों जो भी अदारे हैं जिनके पास लोगों के लिए साधन है वे भी लूट जाते हैं दरअसल चीज तो यह है कि जहाँ हम यह कानून पास करने जा रहे हैं उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है उसको भी

किसी तरह से खत्म किया जाये खासतौर पर जो पढ़े लिखे भाई है या जो बगैर पढ़े लिखे गरीब भर्षी है जिनको आजकल रोजगार नहीं मिलता है उनके लिए जब हत हम रोजगार का इन्तजाम नहीं करेगे तब तक चाहे कानून भी बना दे यह भिक्षावृत्ति नहीं हटेगी। अगर इस प्रकार के कानून लागू भी कर तो भिक्षावृत्ति नहीं हटेगी। अगर इस प्रकार के कानून लागू भी करें तो भिक्षावृत्ति के स्थान पर हिंसावृत्ति आयेगं मेरे विचार में बीमारी को असल ईलाज तो तभी होगा जब कानून क जिरिए से भिक्षावृत्ति को खत् कतो कर ही दिया जाये लकिन इसके साथ हिंसावृत्ति की जो वृत्ति बढ़ती जा रही है इसको भी रोका जाये ताकि आजकल जो हत्यारे बढ़ रही है वे उस और न जायें आप जातने है आतकल चाहे गरीब हो चाहे पढ़ा लिखा हो वह अपने आपको आधा भूख या आधा नंगा रखने को तैयार नहीं, क्यों वह तरीका अब समाज का खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होगा तो वे खुद अपने हाथ में कानून लेकर उस भिक्षावृत्ति का खत्म हु चुका हैं अगर ऐसा होता तो वे खुद अपने हाथ में कानून ले कर उस भिक्षावृत्ति की तरफ चलेगे।

उपाध्यक्ष महोदया, बहन चन्द्रावती ने सही तौर पर है कि जब लोग दबाव देकर मांगते है तो इससे भिक्षा वृत्ति के साथ मिल जाती है। यहां कहा गया कि वह सखती नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक आदमी पिस्तौल चोरी से हाालि करता है और वह पिस्तौल के दम से मांगत है ते उसमें और इस तरह

सख्ती के साथ मांगन में कोइ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस कानून के जरिये भिक्षावृत्ति 16 आने नहीं छूटेगी। हिंसा वृत्ति और भिक्षा वृत्ति दोनों मिल कर समाज को और भी खराब करती है। जैसे बेबसे गरीब आदमियों को कानून के जरिये उनको उन बुरी आदतों से रोकने जा रह है तो उनके लिये पेट पालने के हम कोई साधन भी जुटाए और उन्हें रोजगार देने का कोई तरीका निकाले, उनको उनकी इच्छा के मुताबिक काम दे जो उनके आसान लगे। इएिल अब मुश्किल यह है कि उनको कैसे रोजगार पर लगाये जाये? कुछ भी हो उनहे ऐसा रोजगार दिया जाये कितससे वे थोड़ बहुत गुजारा कर सके, या ऐसा कोई तरीका हम निकले जिससे उनकी भिक्षा मांगने की वृत्ति दूर हो जाये। उपाध्यक्ष महोदया, जैसे मैं कहा है कि बावजूद इन मुश्किलात के हमारे प्रदेश के लोगों के लिए यह बडे फख्दा की बात है कि हमार प्रदेश इस लायक बना है कि हम इसमें ऐसा कानून बनाये जिससे यह भिखारी न रहे।

उपाध्यक्ष: देखिए हमारे पास 25 मिनट है, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है। मिनिस्टर साहब आप कितना टाईम लेगे?

श्री प्रभु सिंह: जितना आप देगे, मैडम।

उपाध्यक्ष: अगर आप थोड़ा टाईम ले तो प्रसत्री देवी जी भी 5 मिनट बोल ले। मैं हाउस को यह बताना चाहती हूं कि

इस ऐक्ट पर मैं भी बोलना चाहती थी। आज से 36 साल पहले पंजाब में मैंने ऐंटी बैगरी बिल को पेश किया था, उस वक्त यह पास नहीं हो सका था। अब यह आ रहा है अब तक कि मैं चेर पर हूँ इसलिए इस पर बोल नहीं सकती।

कई आवाजे: हम इसे पास ही करेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह मैडम, मेरी स्पीच आपके नाम लिख दी जाये।

उपाध्यक्षा: मेरी यह भावना नहीं है। इसके लिये मैं भी गवर्नमैट को दिल खोल कर बधाई दे दूँ कि मेरी जो 36 साल पहले भावना थी वह आज पूरी हो रही है।

श्रीमती प्रसन्नो देवी (इन्दरी): उपाध्यक्ष महोदया, आज सरकार हाउस के सामने जो भिक्षा वृत्ति का बल आई उसके लिए मैं सराकर का बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि यह इसलिए बहुत जरूरी थी कि आम तौर से यह देखने में आता हज़ै कि कुछ लोग गरीब बन कर बच्चों को उठाना शुरू कर देते हैं। वे इन बच्चों को कसे दिन भर भीख मंगवते हैं और उनके द्वारा मांगी गई भिक्षा से वे शराब वे दूसरी चीजों के नशे करते हैं जो बच्चे हिन्दुस्तान के अच्छे नागरिक बन सकते हैं उन बच्चों से ये इस किस्म का काम करवाते हैं। ठग औ जब कतरे किन किन हालात में उनको ले जाते हैं, इस चीज को देखते हुए इस बिल का लोने से बहुत अच्छा रास्ता खुल जायेगा क्योंकि इन्हीं बच्चों नक कल का

हिन्दुस्तान को संभालना है। कई बार यह देखने में आत है कि कई औरते बच्चों को गोद में लिये ओती है। ओर वे भीख मांगती फिरती है। इस चीज का इन औरतों परओर उनके बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। इस बिल को लोने से उनके लिये यह एक अच्छी चीज हो जायेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपक जरिये सरकार से प्रार्थना करनाचाहती हूं कि जो किस्म की बेसहारा औरते है जिन को कोइ काम नहीं मिलता और इस वजह से उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती है हो उनके लिये सरकार कोई धन्धा चालू करें ताकि वे अपनी रोटी कम करके इस भिक्षा वृत्ति से अपने आपको दूर हटाये। कुछ लोग ऐसे होते है जो गुंगे या अन्धे है या उनके हाथ पैर नहीं है उनके लिये मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि कुछ आश्रम खोले जाए जो किसी हालत में काम न मिलने की वजह से भीख न मांगे। सरका इस चीज को भी देखे कि पंजाब और दिल्ली में भिक्षा वृत्ति बन्द करने के बाद जितने भी भिखमगे थे वे हरियाणा में इक्ठे हो गये है यह जो बिल सरकार लाई है यह बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। इस के लिये मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूं कि आपेन मुझे बोलने का समय दिया।

श्री दया कृष्ण (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिब, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपेन मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं कुछ बाते अर्ज करना चाहता हूं। यह देखते है इस किस्म का बिल सरकार को लाना पड़ा है हामरे देश के अन्दर आज दो वर्ग बन

गये हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। जो गरीब है वह बेचारा मांग करके अपना गुजारा करना चाहता है, लेकिन इस बिल के जरिये हम उनको मांगने की ईजाजत नहीं देते। मैं इस बात पर बिल्कुल एकमत हूँ कि वे लोग जो बदमाशी या धींगा मुशती से बच्चों को उठाकर भीख मागने पर मजबूर करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाये और उनके खिलाफ मुकदमें बनाये जाये। लेकिन बहुत से आदमी ऐसे हैं, बहुत से आदमी, बहुतसी बूढ़ी औरतें और बहुत से बच्चे जो बेरोजगार हैं आखिर हमारे शहरी हैं, उनके पास करने के लिये कोई काम नहीं है। उनके लिये काम का और रहन साहन का कोई प्रबन्ध करें और उनकी हालत सुधार करे। अगर सरकार उनकी हालत को सुधार नहीं सकती, उनको रोजगार दे सकती, कपड़ा नहीं दे सकती, मकान नहीं दे सकती और फिर ऊपर से जो किस्म की सजा दे तो यह मेरे ख्याल से गलत बात है। भिखारी की जो इसमें दी है वह काबले तरमीम है इसको भिखारी की डैफिनिशन लिखा हुआ है। जो आदमी घरों में जाकर चीज भी बेचेगा या पटरियों पर अपना समान बेचता है वह भी भीख मंगियों की डैफिनिशन में आ जाता है।

प्रभु सिंह: इसमें ऐसा नहीं है।

उपाध्यक्ष: मिनिस्टर महोदय अपनी स्पीच में 2 बी (1) के बारे में बतायें कि इसमें सैलिंग आटिकल्ज का क्या मतलब है?

श्री दयाकृष्ण: मै समझता हूं कि इसके कुछ कमियां है इन कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। जो बेसहारा लोग है उनको कम देना चाहिये, सहूलियतें देना चाहिये और इनकी रिहायश का प्रबन्ध होना चाहिये, न कि उन के ऊपर कोई पाबन्दी लगाई जाये या मुकदमें चलाये जायें।

श्री प्रभु सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै तो सिर्फ दो-तीन मिनट ही लूंगा। सरकार की तरफ से जो भिक्षा वृत्ति के खिलाफ बिल लाया गया है, इसकी आपोजीशन वालों ने भी तारीफ की हैं दो तीन चीजें इसमें बतानी जरूरी हो गयी है, जैसे हमारे भाई चौधरी लाल सिंह ने कहा कि वह जो बेरोजगार है या अपाहिज है, लूले-लंगड़े है, सरकार उनका क्या करेगी? मै यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ही इन बातों का प्रबन्ध किया है कि जो लम्बे तगड़े काम करने लायक आदमी होंगे, नको दस्तकारी बगैरा सिखाने के लिए एक अलग से सेंटर खोलेंगे और जो लंगड़े लूले या अपाहिज है उनके लिये अलग से सेंटर बनाये जायेंगे जिससे उन्हें रोटी कपड़ा मिलेगा, वे पढ़ सकेंगे और उन्हें डाक्टरी सुविधा भी मिलेगी। यह सरकार ऐसे अपाहिजों और बेकार भिखारियों के लिए 32 लाख रूपया पहले ही ऐस्टिमेट में रख चुकी है। कई तरफ से यह भी जिक्र हो रहा था कि जो बांस पर नट बगैरा चढा कर तमाशा दिखाते है वे भी इस ऐक्ट में आ जायेगी। इस बारे में मै कहना चाहता हूं कि मै मानता हूँकि वह एक हुनर है मगर बास पर चढ कर हुनर दिखाते दिखाते वे यह

नही सोच सकते कि किसी वक्त वे महल बना सकेंगे और इस तहर से उनके बच्चे भी तालीम हासिल नहीं कर पाते। जब हम समाजवाद का नारा लगा रहे हैं तो इस नारे का पूरा करने के लिए हमारी सरकार 32 लाख रुपये का खर्च अपने सिर पर लिया है। जहां तक इस बिल का लागू करने का सम्बन्ध है, मैं आश्वान दिलाता हूँ कि गवर्नर साहब के दस्तखत होते ही फौरन एक मिनट बाद हम इसे लागू कर देंगे। जो कुछ श्री दया कृष्ण जी ने कहा उसे बारमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ किया गया है वह सब कुछ सोच समझ कर बड़ी अम्लमन्दी से किया गया है। यह अकसर दिखाया गया है कि कुछ लोग सड़कों पर तीन तीन आने के पत्रे से लेर बैठ जाते हैं और लोगों की किस्मतें बताते हैं तथा राम को 10-10 रुपये तक कमा लेते हैं। इसे अलावा लोग बन्दर नचाते हैं, रीछ नचाते हैं और पैसे बटोरते हैं। अब वे न तो बन्दर नचा कर पैसे ले सकते हैं और न ही रीछ वगैरा नचाकर पैसे ले सकते हैं। समाजवाद के अन्दर ये लोग मेहनत करें और पैसा कमायें। जो मजदूर हैं और बेरोजगार हैं उनको हम दस्तकारी सिखायेंगे और लोन देंगे ताकि वह अपनी रोजी कमा सकें और एक अच्छे शहरी बन सकें। मैं चाहूंगा कि अब इसको पास करवा दिया जाय। धन्यवाद।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Prevention of Beggary Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is

That sub clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 32

Deputy Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 32 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That sub clause (1) of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker; Question is-

That Title be the Title of the Bill,

The motion was carried.

Sh. Parbhu Singh: Madam, I beg to move-

That the Haryana Prevention of Beggary Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Prevention of Beggary Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That Haryana Prevention of Beggar Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Prevention of Beggar Bill be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House stands adjourned till 2-00 P.M. on Monday, the 15th February, 1971.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P.M. on Monday, the 15th February, 1971.)